नया साल नयी उम्मीद

यूं तो पूरे विश्व में नया साल अलग-अलग दिन मनाया जाता है, और भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में भी नए साल की शुरूआत अलग-अलग समय होती है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरूआत मानी जाती है। चूंकि 31 दिसंबर को एक वर्ष का अंत होने के बाद 1 जनवरी से नए अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष की शुरूआत होती है। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में नया साल शुरू होने के उपलक्ष्य में पर्व की तरह मनाया जाता है। चूंकि साल नया है, इसलिए नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए आईडियाज के साथ इसका स्वागत किया जाता है।

नए साल की शुरुआत के साथ देशवासियों को फील गुड का अहसास कराते हुए केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर एक महत्वाकांक्षी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि देश में पहली बार एक नैशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) तैयार की गई है, जिसके तहत अगले पांच वर्षों में 105 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों ने पिछले छह सालों में बुनियादी संरचना विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में आधारभूत संरचना पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही थी।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा दे दिया है। एक जनवरी, 2020 की आधी रात से कश्मीर में एसएमएस सेवा और ब्रॉडबैंड सर्विस को शुरू कर दिया गया है। अब कश्मीर के लोग एक दूसरे को एसएमएस भेज पा रहे हैं और साथ ही सरकारी अस्पतालों में भी अब इंटरनेट सुचारू रूप से काम करने लगा है। समय का प्रवाह अनवरत है। दिन कोई हो, सप्ताह कोई हो, महीना कोई हो या साल कोई हो, वह इन सबकी परवाह किए बिना अपनी गति से बहता-बढ़ता रहता है। वह न हमारी नाकामियों की चिंता करता है और न हमारी उपलब्धियों की। क्या खोया, क्या पाया यह सब उसके लिए बेमतलब है। हम समय के इसी प्रवाह में जीते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बाकी सभी चीजें भी महत्व रखती हैं। समय के इसी प्रवाह की एक सर्द रात नया साल आता है और हमें सोचने, समझने, और फैसले करने का मौका देता है। कंप्यूटर की दुनिया में एक चर्चित शब्द है रीबूट करना। एक क्षण के लिए कंप्यूटर को बंद कीजिए और फिर से चला दीजिए। बस इतने से कंप्यूटर अपनी पुरानी सुस्ती और बाधा बने पुराने कबाड़ को उतार फेंकता है और फिर नवजीवन के साथ सक्रिय हो जाता है। नया साल भी हमारे लिए अपने जीवन को रीबूट करने का मौका होता है। अगर हम तय कर लें, तो यह ऐसा मौका हो सकता है, जिसमें हम पुरानी बलाओं से पीछा छुड़ाकर नए संकल्पों से जुड़ सकते हैं, नई मंजिलों की ओर बढ़ना शुरू कर सकते हैं। साल 2020 हमारे लिए इसी कारण से महत्वपूर्ण है कि इस समय हमारे पास पिंड छुड़ाने के लिए बलाएं भी बहुत सारी हैं और ऐसी मंजिलें भी बहुत सी हैं, जहां जाने का कोई विकल्प फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन उन राहों पर हमारे अभी कदम भी ठीक से नहीं बढ़े हैं। नया साल उस समय आया है, जब देश के एक बड़े हिस्से में सर्दी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और दूसरी तरफ कई तरह के असंतोष न सिर्फ सतह पर आ रहे हैं, बल्कि उग्र होते हुए दिख रहे हैं। लोग अपने हितों को लेकर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आएं, इसे किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन सड़कों पर उनके जमाव की परिणति अगर किसी टकराव में हो, तो इसका अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ शुभ नहीं है। आगे बढ़ते हुए इस देश के ऐसे अंतर्विरोध बहुत सारे हैं, नए साल में हम ऐसे अंतर्विरोधों को शांति और सहानुभूति से अंतिम विदाई देने का संकल्प ले सकते हैं। बेशक यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ साल में ऐसी ताकतें काफी प्रबल हुई हैं, जो ऐसे दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को न सिर्फ बढ़ाने में यकीन रखती हैं, बल्कि इन्हीं पर वे अपनी रोटी भी सेंकती हैं। सात साल पहले जब निर्भया की निर्मम हत्या के बाद पूरा देश उबाल पर था, तब इसी स्तंभ में हमने यह उम्मीद जताई थी कि इसी उबाल से कोई नया रास्ता निकलेगा। 2019 ने हमें यह बताया कि उस दिशा में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है।

भरत सिंह चौहान
संपादक

साल 2020 हमारे लिए इसी कारण से महत्वपूर्ण है कि इस समय हमारे पास पिंड छुड़ाने के लिए बलाएं भी बहुत सारी हैं और ऐसी मंजिलें भी बहुत सी हैं, जहां जाने का कोई विकल्प फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन उन राहों पर हमारे अभी कदम भी ठीक से नहीं बढ़े हैं। नया साल उस समय आया है, जब देश के एक बड़े हिस्से में सर्दी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है और दूसरी तरफ कई तरह के असंतोष न सिर्फ सतह पर आ रहे हैं, बल्कि उग्र होते हुए दिख रहे हैं। लोग अपने हितों को लेकर बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आएं, इसे किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है, लेकिन सड़कों पर उनके जमाव की परिणति अगर किसी टकराव में हो, तो इसका अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब कुछ शुभ नहीं है।

पुष्पांजली टुडे

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

वर्ष 05, अंक 11, जनवरी 2020,

मूल्य 30 रु, पृष्ठ 44

संरक्षक	बहादुर सिंह चौहान
संपादक	भरत सिंह चौहान
प्रबंध संपादक	शैलेश सिंह कुशवाह
कार्यकारी संपादक	राजानल शर्मा
सहायक संपादक	धीरेंद्र सिंह दांगी
उपसंपादक	अरविंद सिंह नरवरिया
	अर्पित गुप्ता
	प्रदीप नागेन्द्र सिकरवार
	विपिन तोमर,
	शशिभूषण चौहान (मप्र)
कानूनी सलाहकार	एड. आर. के. जोशी
ऑल इंडिया रिपोर्टर	अन्जू भरमोरिया
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी	आर एस रजक
मप्र ब्यूरो चीफ	पंकज त्रिपाठी

ब्यूरो प्रमुख

नरेन्द्र शर्मा	:	हरियाणा
बलभद्र सिंह सेठिया	:	छत्तीसगढ़
संदीप प्रधान	:	ग्वालियर संभाग
राजा दुबे	:	सीहोर
केवल राम मालवीय	:	इंदौर
सोनू कुमार माथुर	:	एटा, (उत्तर प्रदेश)
प्रवेन्द्र सिंह	:	आगरा (उत्तर प्रदेश)
अरूण कुमार साहू	:	सतना
मंगल सिंह परमार	:	धौलपुर राजस्थान)
केशव प्रसाद शर्मा	:	मुरैना
सादिक मिश्रा	:	खरगौन
मोहन मांझी	:	गोहद
अमित शर्मा	:	ग्वालियर
सुरजीत राजावत	:	ग्वालियर
आदित्य सिंह		पोरसा

कार्यालय

ए-ब्लॉक 404 भाऊसाहब पोतनीस, इन्क्लेव, मुरार रोड

गोले का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश

संपर्क: 8269307478

www.pushpanjalitoday.com

Email-pushpanjalitoday@gmail.com

इस अंक में

समाजसेवा के लिए समर्पित पुष्पांजली जनकल्याण फाउंडेशन 20

नए साल और दशक के लिए एक संकल्प लें 10

दिल्ली केजरीवाल का जलवा 17

स्वच्छता में इंदौर अव्वल 14

अब और मजबूत होंगी सेनाएं 13

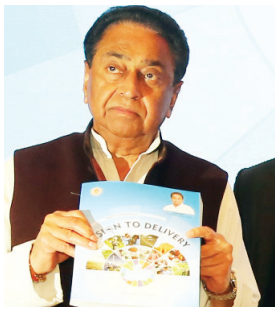

विजन टू डिलेवरी रोड मैप 24

क्या हैं गणतंत्र के सही मायने 37

बिग बी को सम्मान... 39

सलमान संग काम- दीपिका 40

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक-भरत सिंह चौहान। कंचन प्रिंटिंग प्रेस-निम्बालकर का बाड़ा, तेली की बजरिया नियर पी.एंड.एन. बैंक नया बाजार लश्कर जिला ग्वालियर म.प्र .से मुद्रित तथा, दीपू इलेक्ट्रोनिक्स हनुमान मंदिर के पास, गोवर्धन कॉलोनी, भिण्ड रोड, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) से प्रकाशित। सम्पादक-भरत सिंह चौहान। समाचारों के चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार दूरभाष : 8269307478 Mail: pushpanjalitoday@gmail.com Web. www.pushpanjalitoday.com

स्पोशल रिपोर्ट

निर्भया को इंसाफ

निर्भया को मिला न्याय

“ अब 22 जनवरी को सुबह सात बजे दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया के बलात्कारियों और हत्यारों को फांसी दे दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी होते ही वह मामला अपने अंजाम तक पहुंचता दिखने लगा, जो पिछले सात साल से भी ज्यादा समय से समाज के सीने पर पड़ा हुआ था। यह एक खराब उदाहरण बन गया था।

जब भी देश में बलात्कार या महिलाओं से अत्याचार की कोई घटना घटती थी, तब यही कहा जाता था कि इस तरह की घटनाएं कैसे रुक सकती हैं, जब इतने समय बाद भी हम निर्भया के हत्यारों को सजा तक नहीं दे सके। हालांकि सभी लोग भले ही इससे सहमत न हों, पर आम धारणा यही है कि कड़ी सजा किसी भी अपराध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होती है। अपराधी तत्व किसी महिला के खिलाफ किस हद तक बर्बर हो सकते हैं, निर्भया कांड इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसीलिए यह माना जाता रहा है कि अगर हम निर्भया के हत्यारों को शीघ्र सजा नहीं दे सके, तो यही धारणा बनेगी कि बहुत जघन्य अपराध करके भी बचा जा सकता है या फिर सजा को लंबे समय तक के लिए टाला जा सकता है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि निर्भया जैसे कांड के दोषियों को दी जाने वाली सजा भी अपने आप में एक मिसाल बननी चाहिए। इस मामले में छह आरोपी थे। एक अवयस्क था, जिसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। एक अन्य आरोपी राम सिंह ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। अगर कोई और बाधा नहीं आती है, तो बाकी चार के लिए अब दो सप्ताह का ही जीवन शेष है। दोषी पक्ष समाज की इस बेसब्री को समझ रहा था, इसलिए उसकी कोशिशें यही थीं कि सजा को जितना हो सके, टाला जा सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड पर मुहर लगा दी, तब भी उसे टालने की कोशिशें चलती रहीं। यह सच है कि भारत की न्याय-व्यवस्था अंतिम समय तक मृत्युदंड पाए दोषी को अपना बचाव करने के विकल्प देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसी सजा को अनंत काल तक टाला जा सके। हालांकि कोशिशें कुछ इसी तरह की हो रही थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पिछले कुछ समय से सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी। पिछले दिनों जब एक दोषी के अवयस्क होने के मुद्दे को फिर से अदालत में लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मामला तो खारिज किया ही, याचिका दायर करने वाले वकील पर ही जुर्माना लगा दिया। जाहिर है, यह सजा अगर दी जाती है, तो एक उदाहरण तो बनेगा ही। हालांकि यह अभी दावे से नहीं कहा जा सकता कि इससे बलात्कार की वारदात खत्म या कम हो जाएंगी। निर्भया मामले के बाद देश में बलात्कार से संबंधित कानूनों में कई बड़े बदलाव किए गए। बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी किया गया। इन सबके पीछे सोच यही थी कि दंड का भय सिरफिरे लोगों को अपराधी बनने से रोकेगा। लेकिन अभी पिछले महीने ही जिस तरह की घटनाएं देश में हुईं, उन्होंने बताया कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानूनी बदलावों का संदेश जितना आगे नहीं गया था, उतना इस सजा का जाएगा। इसके आगे की जरूरत महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने की है।

नागरिकता कानूनः देश भर में हिंसा और बवाल

“ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिस तरह की हिंसक घटनाएं देश के कई राज्यों में घटी, उनका जितनी निंदा की जाए उतना कम है। असल में जिस कानून का देश के नागरिकों से कुछ लेना देना ही नहीं है, उस पर हिंसा समझ से परे है। दरअसल सरकार के हर निर्णय का विरोध करना विपक्ष ने अपना धर्म समझ लिया है। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए षड्यंत्र के तहत जब राजनीतिक दल आम लोगों को उसमें शामिल कर विरोध करने लगते हैं तो अनियत्रिंत भीड़ विस्फोटक स्थितियां पैदा कर देती है।

लोकतंत्र में मतभेद जताना या सरकार के किसी फैसले का विरोध करना जनता का मूल अधिकार माना जाता है। इसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अलग नजरिया रखने वाले लोगों की संख्या कितनी है। दरअसल, यह सिर्फ लोकतंत्र की ही विशेषता है कि वह अल्प संख्या वालों को भी विरोध और प्रदर्शन के पूरे अधिकार देता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है, जब ऐसे विरोध और प्रदर्शन के दौरान हिंसा की वारदात हो जाती है। लोकतंत्र में विरोध को व्यक्त करने के मंच और सामाजिक-राजनीतिक स्पेस देना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसकी इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी होती है कि वह समाज में किसी भी तरह की हिंसा न होने दे। जब हिंसा हो जाती है, तो सरकार के सामने सबसे आसान विकल्प यही होता है कि वह उसे रोकने के लिए विरोध और आंदोलन के स्पेस को कम कर दे। यानी हिंसा करने वाले एक तरह से अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। इस समय देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं, वे इसी खतरनाक राह को पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इस बात का ख्याल रखा कि शांति बनी रहे, वहां हिंसा नहीं भी हुई, लेकिन तनाव के माहौल में हिंसा की खबरें ही सुर्खियां बनती हैं और यही हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हो रहे आंदोलन से यह उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वह समाज में एक विमर्श को शुरू करके वैकल्पिक सोच के दायरे को मजबूत बनाता, लेकिन यह विमर्श अब पुलिस पर पथराव और जवाबी कार्रवाई में लाठीचार्ज, आंसू गैस व गोलीबारी में सिमट गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हम ऐसा पहले भी कई आंदोलनों में देख चुके हैं।

हाल-फिलहाल में गोरक्षा के नाम पर दिखी सक्रियता में भी यही भेड़चाल नजर आई थी। सबसे दुखद यह है कि यह सब ऐसे देश में हो रहा है, जिसे दुनिया भर में अहिंसक आंदोलन की सबसे मजबूत परंपरा शुरू

करने के लिए जाना जाता है। ऐसा सिर्फ आजादी के आंदोलन में नहीं, उसके बाद भी कई बार हुआ है। कुछ साल पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ चले देशव्यापी आंदोलन में भी अहिंसक तेवर हर जगह दिखाई दिया था।

जैसाकि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, तो इसे जानने की भी जरूरत है। जनगणना आयोग ने कहा है कि एनपीआर का उद्देश्य देश के प्रत्येक 'सामान्य निवासी' का एक व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है। देश में बड़ी आबादी ऐसी भी है, जो एनआरसी और एनपीआर में अंतर नहीं समझती। इसलिए इसमें अंतर समझना-समझाना आवश्यक है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एनपीआर देश में रहने वाले निवासियों का राष्ट्रीय डाटा तैयार करने की रूटीन कवायद है।

आबादी के स्तर पर बदलाव स्वाभाविक हैं, क्योंकि कोई दिवंगत होता है, तो कोई जन्म लेता है, कोई कामकाज के सिलसिले में अपना पुश्तैनी घर, गांव या कस्बा भी छोड़ता है। बदलाव के ऐसे असंख्य आंकड़े सामने कैसे आएंगे या सरकार की जानकारी में कैसे होंगे? सरकारें और प्रशासन इसी आधार पर योजनाओं और नीतियों के प्रारूप तय करते हैं। लेकिन चूंकि देश में नागरिकता कानून से लेकर एनआरसी की बातें चल रही हैं, ऐसे में सरकार के हर कदम को विपक्षी दल उससे जुड़ा बता रहे हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

ऐसा नहीं है कि एनपीआर जैसी कवायद केवल भारत में ही होती है। विश्व के अधिकतर देशों में इसका प्राविधान है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय एनपीआर की व्याख्या इस तरह करता है- एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र) नियम-2003 के प्राविधानों के तहत स्थानीय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एनपीआर में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

एक सामान्य निवासी एनपीआर के उद्देश्यों के तहत वह व्यक्ति है, जो पिछले छह महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या जो अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में निवास करने का इरादा रखता है। इसका उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डाटाबेस तैयार करना है। डाटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमीट्रिक विवरण शामिल होंगे। प्रत्येक निवासी के लिए यह जनसांख्यिकीय विवरण आवश्यक है, जिसके तहत नाम, मां-पिता या पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता से लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी देनी होगी।

आबादी के आंकड़ों के हिसाब से योजनाओं का प्रारूप बनता है और वो जमीन पर उतर पाती हैं। गौरतलब तथ्य यह है कि भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं। कुछ भटकी प्रजातियां भी हैं और कुछ हजार सिर्फ अनेक फसल काटने वाले समुदाय हैं। कई लाख बेघरबार और भीख मांगकर गुजारा करनेवाले हैं। ये सभी अस्थायी और अस्थिर निवासी हैं। बेशक वे सभी 'भारतीय' ही होंगे। योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा वहां भी एक संवेदनशील समस्या है। तो समय-समय पर उनका हिसाब-किताब क्यों नहीं होना चाहिए? वर्ष 2003 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने एक नियम बनाया था- नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्ड जारी करना। लिहाजा एनपीआर देश के स्वाभाविक निवासियों का रजिस्टर है। इसका पालन यूपीए सरकार ने भी पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर किया।

जनसंख्या का आंकड़ा भी जानना जरूरी है। सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक अनुपात के यथार्थ भी सामने आने चाहिए। सवाल है कि इस विश्लेषण में ऐसी कौन-सी साजिशें छिपी हैं, जिनके मद्देनजर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केरल की वामपंथी सरकार ने एनपीआर की प्रक्रिया लागू करने से इन्कार किया है। कांग्रेस भी खामोश है। एनपीआर की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2019 को जारी की थी। उसके बाद लगभग सभी राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह

और सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इन तथ्यों को स्पष्ट कर चुके हैं। सरकार यह भी स्पष्ट दावा कर रही है कि एनआरसी और एनपीआर में कोई संबंध नहीं है।

एनपीआर का डाटाबेस एनआरसी में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ओवैसी सरीखे नेता किस आधार पर यह अफवाह फैला रहे हैं कि एनपीआर ही एनआरसी का पहला कदम है? बहरहाल, कई विपक्षी दल इसे भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में लग गए। अच्छा हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह ने समय पर सफाई दे दी। देश को मालूम होना चाहिए कि उसके यहां कौन-कौन रहते हैं। विपक्षी दलों व अन्य संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वह इस मामले में राजनीति करने की बजाय लोगों को सही जानकारी दें। हर मामले में राजनीति और विवाद से देश और देशवासियों का नुकसान होना लाजिमी है। जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आप विकास का खाका नहीं खींच पाएंगे। राजनीतिक दलों का ध्यान देश की जनता की भलाई के बारे में सोचना होना चाहिए। देश की सुरक्षा और विकास से जुड़े कार्यों में बेवजह का विवाद पैदा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। गृह मंत्री इस मामले में अपनी राय एक साक्षात्कार के माध्यम से देश के समक्ष साफ कर चुके हैं, अब इ अब इस मामले में राजनीति बंद होनी चाहिए।

यूपी में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, भारी नुकसान

उत्तर प्रदेश सरकार ने 130 दंगे के आरोपियों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में पिछले दिनों हुए प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई थी, अनुमान लगाया गया है कि उसमें सार्वजनिक संपत्ति का 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। कहा जा रहा है कि अब यह नुकसान आरोपी बलवाइयों से वसूला जाएगा। इसके लिए जगह-जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, यहां तक कि पहचान के लिए आरोपियों की तस्वीरों वाले पोस्टर भी पुलिस ने दीवारों पर चिपकाए हैं। जिस तनावपूर्ण माहौल के कारण पिछले दिनों उत्तर प्रदेश समेत देश के कई अन्य हिस्सों में हिंसा हुई थी, वह माहौल अभी भी बरकरार है। लोग आगे ऐसी घटनाओं से बाज आएं, मुमकिन है कि इसी सोच के साथ प्रशासन ने यह कार्रवाई की होगी। पर यह कार्रवाई अंत में किस परिणति तक पहुंचेगी, अभी नहीं कहा जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली प्रदर्शन करने वालों या दंगाइयों से की जाए, यह विचार अपने आप में नया नहीं है, कई बार अदालतों ने भी इसके लिए कहा है। इसकी कई बार कोशिश भी हुई, लेकिन कहीं भी सचमुच इसकी वसूली हो पाई हो, ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है। साल 2012 में मुंबई के आजाद पार्क में हुई एक रैली के दौरान हिंसा हुई थी। बाद में यह पाया गया कि उस हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को लगभग पौने तीन करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचा था। इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस ने वसूली-नोटिस भी जारी किया। लेकिन वसूली हो पाई, ऐसी खबर कभी नहीं आई। यह शायद बहुत आसान भी नहीं है। मामला अंत में अदालत में जाएगा और वहां सीसीटीवी फुटेज सुबूत के तौर पर कितने स्वीकार्य होंगे, यह भी नहीं कहा जा सकता। दंगा रोकने के लिए ऐसे कदम कुछ हद तक प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन वसूली अपने आप में दंगे की सजा नहीं हो सकती। अगर हम दंगे के बाद की सारी कार्रवाई को सिर्फ वसूली तक सीमित कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हम इसे आर्थिक अपराध बना देते हैं, जबकि सार्वजनिक हिंसा और दंगा पूरे समाज को भयाक्रांत करने वाला अपराध है। इसे सिर्फ आर्थिक नुकसान की नजर से नहीं देखा जा सकता। सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का तो आकलन हो सकता है, लेकिन घायल होने वालों और अपनी जान गंवाने वालों के नुकसान का आकलन आप कैसे करेंगे? दंगा सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, यह एक सामाजिक अपराध है, जो प्रत्यक्ष नुकसान से कहीं ज्यादा समाज को विषाक्त करने का काम करता है। इसकी सजा कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। हम आमतौर पर दंगाइयों को सजा नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह उम्मीद भी व्यर्थ है कि उनसे नुकसान की वसूली हो सकेगी। बात सिर्फ इतनी नहीं है। अपने देश में दंगे सिर्फ दंगे नहीं होते, उनके पीछे अक्सर कोई न कोई राजनीति होती है। राजनीतिक दल चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में, उनकी दिलचस्पी दंगों का राजनीतिक लाभ लेने में ज्यादा होती है, दंगाइयों को दंडित

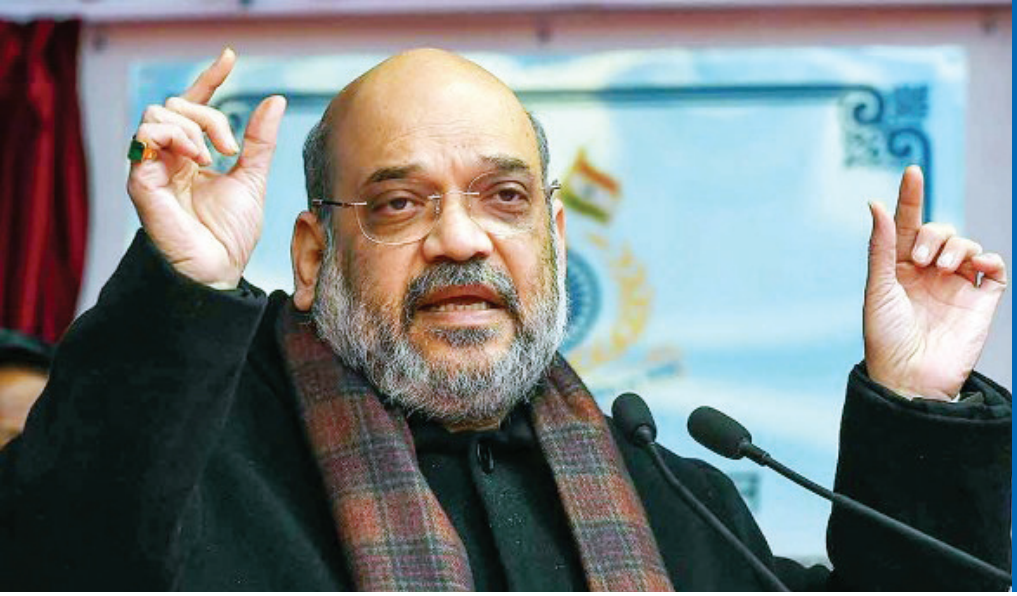

अमित शाह बोले

एनपीआर की वजह से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी

केंद्रीय मंत्रिमंडल से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अनुमति मिलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि इसका एनआरसी से संबंध नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि देश में एनआरसी पर कोई बात नहीं हो रही है। इस पर बहस की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनआरसी पर बयान को सही बताया और कहा कि एनआरसी पर कैबिनेट और संसद में कोई चर्चा नहीं हुई है।

अमित शाह ने कहा कि अगर एनपीआर में किसी नागरिक का नाम नहीं दर्ज हो पाता है, तो इससे उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपा के घोषणापत्र में एनआरसी की बात होना और संसद में इस पर चर्चा होना अलग अलग बातें हैं। विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है, वह एनपीआर, एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर राजनीति खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 'पॉलिटिक्स और कम्युनिकेशन' में अंतर होता है। केंद्र के नोटिफेकेशन के बाद राज्यों ने भी नोटिफिकेशन निकाले, यह कम्युनिकेशन है। लेकिन पॉलिटिक्स यह है कि सीएए के कारण बवाल खड़ा हुआ। अब चूंकि यह बवाल थम रहा है और लोग इसे समझ रहे हैं, तो एनपीआर का बवाल खड़ा करो। सीएए पर प्रदर्शन भी वहीं ज्यादा हुए, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए रहते हैं।

डिटेंशन सेंटर हमारे समय का नहीं

डिटेंशन सेंटरों पर शाह ने कहा कि अगर कोई दूसरे देश से गैर-कानूनी ढंग से देश में आ जाता है, तो उसे जेल में नहीं रखा जाता है। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं। इन डिटेंशन सेंटरों का एनआरसी से लेना-देना नहीं है। साथ ही बताया कि असम में केवल एक डिटेंशन सेंटर चल रहा है। जो सेंटर चल रहा है उसे मौजूदा भाजपा सरकार में तो बनाया भी नहीं गया।

एनपीआर कांग्रेस की पहल थी

शाह ने यह भी कहा कि एनपीआर की प्रक्रिया कांग्रेस ने 2010 में शुरू की थी। 2004 में इसका कानून बनाया था। भाजपा ने इसे जनगणना के साथ जारी रखने का निर्णय लिया है, यह पार्टी के घोषणापत्र में नहीं था। वहीं उन्होंने साफ किया कि इसमें किसी का नाम शामिल नहीं होता है तो उसकी नागरिकता की वैधता पर प्रश्न नहीं उठेंगे, यह एनआरसी से अलग है।

एनपीआर-एनसीआर अलग-अलग

शाह ने कहा कि एनपीआर जनसंख्या का रजिस्टर है। इसके आधार पर अलग-अलग योजनाओं के आकार तय होते हैं। एनआरसी में हर व्यक्ति से साक्ष्य मांगा जाता है कि आप किस आधार पर भारतीय नागरिक हैं? दोनों प्रक्रियाओं का एक-दूसरे से कोई लेनादेना नहीं है और न ही दोनों एकदूसरे के सर्वे को अपने काम में ले सकते हैं। दोनों के लिए कानूनी आधार भी अलग अलग हैं।

एनपीआर की जरूरत इसलिए

उन्होंने कहा कि एनपीआर की जरूरत इसलिए है कि हर 10 साल में अंतरराज्यीय स्तर पर जनगणना में काफी बदलाव आ जाते हैं। नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाते हैं। इन बदलावों के मुताबिक योजनाएं बनाने के लिए एनपीआर आधार होता है।

एप के जरिए जानकारी, साक्ष्य नहीं देना होगा

उन्होंने कहा कि एनपीआर के तहत भारत में रहने वाला हर कोई भी व्यक्ति एक एप में अपनी जानकारियां देगा। उसे इन जानकारियों के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। अगर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, तो उस जानकारी के स्थान को खाली छोड़ सकते हैं। इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि क्या आप भारत के नागरिक हैं? बल्कि घर के आकार, पशुधन, आदि जैसी जानकारियां ली जाएंगी।

जेएनयू में हिंसक और टकराव

जेएनयू में हुई हिंसा को किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुई मारपीट की तरह नहीं देखा जा सकता, हालांकि इसकी ऐसी ही शक्ल देश के सामने पेश की जा रही है। विश्वविद्यालयों से छात्रों की बेचैनी और संगठनों के हिंसक टकराव की खबरें पिछले कुछ सालों से लगातार आ रही हैं, लेकिन पिछले पंद्रह-बीस दिनों में हुई ऐसी घटनाओं को अलग रोशनी में ही देखा जा सकता है। पहले जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और अब जेएनयू में हुई हिंसक घटनाओं के ब्यौरे बताते हैं कि इनके ज्यादा बड़े सूत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर हैं। इन घटनाओं में मुख्य भूमिका सरकारी तंत्र और उसके नजदीक रहकर उत्पात मचाने वाले बाहरी तत्वों की बताई जा रही है।

शासन के विवादित फैसलों से समाज में फैले असंतोष और उसे दबाने की कोशिशों का कुछ नाता भी इन घटनाओं से दिखता है, हालांकि इस बारे में ठोस जानकारी तटस्थ जांच से ही सामने आ सकती है। बीते रविवार बाहरी नकाबपोशों का जेएनयू में घुस आना एक ऐसा तथ्य है, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। देश की राजधानी में स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था वाले एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में लाठी, डंडे, रॉड लिये गुंडे अचानक घुस आएं और वहां घंटों तांडव मचाकर सुरक्षित निकल जाएं, यह बात आसानी से गले नहीं उतरती। जेएनयू प्रशासन से ही नहीं, दिल्ली के पुलिस तंत्र से भी कुछेक असहज कर देने वाले सवालों के जवाब अपेक्षित हैं। यह तो ठीक है कि पुलिस ने जामिया वाली गलती नहीं दोहराई और बाहरी हमले की सूचना होने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन के बुलावे का इंतजार किया। लेकिन उसके कैंपस में पहुंचने के बावजूद एक भी नकाबपोश गुंडा पकड़ा नहीं जा सका, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ हमले पुलिस की मौजूदगी में भी हुए- यह बात दिल्ली पुलिस की छवि से मेल नहीं खाती। यूनिवर्सिटी के सभी गेटों पर पहरे बिठाकर गुंडों को बाहर जाने से रोकना भी क्या इतना कठिन काम था? पुलिस कह रही है कि उनमें से पांच-छह की पहचान कर ली गई है, लेकिन अभी तो वह यह बताए कि अपवाद स्वरूप भी उनमें से कोई पकड़ा क्यों नहीं गया। दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बिठा दी गई है, लेकिन खुद पुलिस की ढिलाई के पीछे किसका हाथ था, यह जानकारी न्यायिक जांच में ही निकल कर आ सकती है। अच्छा होगा कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार इसे हल्के में न ले। देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में सौ-पचास नकाबपोश अगर मार-काट मचाकर बेदाग निकल जाते हैं, तो ऐसा किसी भी हाई सिक्योरिटी कैंपस में हो सकता है- कोई मंत्रालय, कोई मीडिया संस्थान, कोई ऐतिहासिक-सांस्कृतिक धरोहर। सरकार अगर राजधानी में अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखना चाहती है, तमाम तरह के षड्यंत्र सिद्धांतों को हवा नहीं देना चाहती तो उसे न्यायिक जांच का आदेश देकर सचाई सामने आ जाने देना चाहिए।

अमेरिका और ईरान में होगा युद्ध ?

अमेरिका और ईरान के बीच पहले अच्छी दोस्ती थी. लेकिन तेल की सियासत ने इसको इस कदर दुश्मनी में बदला कि अब ये एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं. सत्तर के दशक से पहले के समय में ईरान और अमेरिका के बीच कई स्तरों पर गहरी दोस्ती थी. लेकिन, सत्तर के दशक के अंत में जब ईरान में इस्लामी गणतंत्र घोषित हुआ, तब से ईरान पर से अमेरिका का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा. अब हालत यह है कि दोनों देश अक्सर एक-दूसरे से लड़ते रहते हैं. अमेरिका ने ईरान के जिस सुप्रीम कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को हवाई हमले में मार दिया है, यह अमेरिका की दादागिरी तो है ही, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचानेवाला कृत्य भी है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती तो पहले से ही छायी हुई है. वहीं अब सुलेमानी की हत्या से मध्य एशिया में अशांति के गहराने की भी आशंका है.

इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत गहरा है और अपने चरम पर है. लेकिन, अब भी इस बात का अंदेशा इतना मजबूत नहीं है कि यह तनाव दोनों के बीच जंग में तब्दील हो जायेगा. ईरान की तरफ से इस हत्या का कोई जवाब भले दिया जा सकता है, जिसके जवाब में अमेरिका फिर कुछ करे, यह सिलसिला चल सकता है, लेकिन आर-पार की जंग के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं. जवाबी हमलों के बीच खाड़ी के देशों में कोई बड़ी जंग छिड़ जाये, इसकी भी संभावना कम है. हालांकि, ऐसी किसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगे कब क्या हो जाये. अगर मात्र जवाबी हमलों का सिलसिला चलता रहेगा, तब तो भारत पर इसका प्रभाव बहुत सीमित होगा. लेकिन, अगर सचमुच ईरान कोई बड़ा जवाबी हमला करता है, जिससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो, तब निश्चित रूप से अमेरिका उसके जवाब में बड़ा कदम उठा सकता है. यह सब अभी भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता और न ही कोई देश चाहेगा कि वह युद्ध की विभीषिका को झेले. ईरान कभी भी अमेरिका की बात नहीं मानता है और परमाणु कार्यक्रम को चलाता रहता है. इसलिए संकट यह भी है कि कहीं परमाणु हमले की तरफ सनक बढ़ी, तो भारत ही क्या पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी. ईरान-अमेरिका तनाव से तेल के दाम बढ़ गये हैं, यह एक तात्कालिक प्रभाव तो है ही, अगर तनाव और गहराता है, तो इसके बड़े प्रभाव भी दिखने लगेंगे. भारत के लिए यह ठीक नहीं होगा. इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही थोड़ी डांवाडोल है, ऐसे में तेल के दाम बढ़ने से उस पर बड़ा असर पड़ेगा. दूसरी बात, इस तनाव की वजह से वैश्विक बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल है, जिसका असर जाहिर है भारत के बाजारों पर भी पड़ेगा ही. अनिश्चितता के माहौल में बाजार कोई रिस्क लेने से डर जाता है, जिससे निवेश और उत्पादन प्रभावित होते हैं.

शैलेश सिंह कुशवाह
वरिष्ठ पत्रकार

आज अमेरिका और ईरान में जो तनातनी का खेल चल रहा है उसका मुख्य कारण तेल का व्यापार है आज दुनिया मैं तरक्की जो दिखाई दे रही है उसका मूल कारण तेल है यदि एक दिन तेल की आवाजाही रुक जाए तो पूरी दुनिया स्थिर हो जाएगी सारी दुनिया के आवागमन के साधन बंद हो जाएंगे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद का भंडार सऊदी अरब इराक ईरान में ही हैं अमेरिका पहले ही इराक और सऊदी अरब पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं अब वह चाहता है के ईरान भी उसकी शर्तें मान ले परंतु ईरान के शासक अमेरिका की मनमर्जी नहीं मानते हैं इसीलिए ईरान अमेरिका की आंखों में किरकिरी की तरह खटकता है समय-समय पर अमेरिका इसके लिए ईरान को आंख भी दिखाता रहता है अमेरिका ने पूरे विश्व में अपने फायदे के लिए अपने नियम कानून थोपते हैं जो कुछ देशों को मान्य होता है तथा कुछ देश इसे नहीं मानते हैं जो देश अमेरिका की शब्दों की अनदेखी करते हैं उसका परिणाम यह होता है कि उसे अमेरिका की दादागिरी झेलना पड़ती है ऐसी घटनाएं विश्व में अनेकों बार देखने को मिली हैं हमने देखा के एक एक आतंकी की वजह से पूरे अफगानिस्तान को अमेरिका की तबाही झेलनी पड़ी इसी प्रकार सद्दाम हुसैन के तानाशाह रवैया के कारण पूरा इराक तबाही के दौर से गुजरा और आज भी वहां अमेरिका अपना अड्डा जमाए हुए हैं इसका मूल उद्देश्य यह है कि अमेरिका इराक के तेल को अपने हिसाब से दोहन कर रहा है इसी तरह खाड़ी के अन्य तेल उत्पादक देशों पर अमेरिका अपने टेरर टैक्स के दम पर मनमानी करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है ऐसे ही अनगिनत देशों पर अमेरिका अपनी शर्तें मनवा ता है जो सरासर गलत है आज विश्व का कोई भी देश अमेरिका की दादागिरी से अछूता नहीं है चाहे शक्ति संपन्न रूस की बात करें रूस के विघटन में अमेरिका का अहम रोल है अगर हम चीन की बात करें तो वहां पर भी अमेरिका अपनी आंखें टेढ़ी करें रहता है जापान जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र भी अमेरिका के हिसाब से चल रहे हैं इसके साथ साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान भारत कनाडा जर्मनी इजराइल जैसे अनगिनत देश अमेरिका के रुख के अनुसार अपनी स्थिति परिस्थिति बदल कर उसके मनमाफिक चलने को बाध्य हैं अमेरिका आज जिस तरह दबाव की रणनीति बनाकर पूरे विश्व में दादागिरी कर रहा है उसका परिणाम आने वाले दिनों में उसे भुगतना पड़ेगा यही कारण है कि ईरान जैसे देश ने उसे आंखें तरेर ना शुरू कर दी हैं अभी कुछ समय पूर्व कोरिया के तानाशाह शासक ने अमेरिका को आंख दिखाई थी फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झुकना पड़ा था आज अमेरिका जिस स्थिति में खड़ा है कहीं ना कहीं वह ईरान के सामने एकदम लड़ नहीं सकता क्योंकि चीन और रूस का दबाव साफ झलक रहा है और यही परिणाम है कि डोनाल्ड ट्रंप दबी आवाज में कह रहे हैं कि हम दुनिया पर युद्ध नहीं थोप सकते उन्होंने नरम रुख करते हुए कहा कि हम शांति के साथ काम करना चाहते हैं दूसरी तरफ ट्वीट कर अपने तीखे तेवर भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस सब के पीछे एक ही मकसद है कि ईरान के तेल भंडार पर कैसे कब्जा किया जाए।

पीएम मोदी ने कहा- हमारे युवाओं को अराजकता-जातिवाद के प्रति नफरत

नए साल और दशक के लिए एक संकल्प लें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60वीं बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं। मोदी ने कहा कि हमारे देश के युवाओं को अराजकता के प्रति नफरत है। वे जातिवाद, अपना-पराया, स्त्री पुरुष में भेदभावों को पसंद नहीं करते हैं। नई पीढ़ी आधुनिक है। नए साल और दशक के लिए एक संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने का आग्रह भी किया है।

मोदी ने कहा- हम 2 दिन बाद 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करेंगे। हमारे देश के युवाओं को अराजकता के प्रति नफरत है। वे जातिवाद, अपना-पराया, स्त्री पुरुष इन भेदभावों को पसंद नहीं करते। हम देखते हैं कि अगर कोई सिनेमा एयरपोर्ट में कतार के बीच में घुस जाता है तो युवा उसे सबसे पहले टोकते हैं। युवाओं में नए प्रकार की व्यवस्ता और सोच परिलक्षित करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरा भरोसा युवा पीढ़ी पर है। इस आधुनिक जेनरेशन में है। उन्होंने विश्वास जताया था कि इन्हीं में से मेरे लोग निकलेंगे। युवावस्था सबसे अहम कालखंड होता है। आपका भविष्य और जीवन इस पर निर्भर करता है कि आप युवावस्था का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत में यह दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि युवाओं का विकास करने वाला साबित होगा। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पर इस दशक में अपने दायित्वों पर चिंतन करें और नए दशक में संकल्प लें। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से हर किसी को प्रेरणा दी है। कुछ समय पहले तक फूलपूर की यह महिला गरीबी से परेशान थीं। लेकिन इनमें अपने परिवार को आगे ले जाने का जज्बा था। महिलाओं ने चप्पल बनाने का काम शुरू किया। इससे महिलाओं ने न सिर्फ अपने राह का कांटा दूर किया, बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाया। लोगों ने महिलाओं से चप्पलें खरीदकर उनकी मदद की। मैंने लालकिले

से 15 अगस्त को आग्रह किया था कि हम लोकल चीजें खरीदें। मेरा फिर से आग्रह है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स को अपनी शान और प्रतिष्ठा से जोड़ सकते हैं, क्या हम इन्हें खरीदकर लाखों के जीवन में समृद्धि ला सकते हैं। क्या हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

2022 को हम आजादी के 75 साल पूरे करेंगे। क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि कम से कम यह दो तीन साल स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बने। जिन चीजों में हमारे लोगों के पसीने की महक हो उसे खरीदने का संकल्प कर सकते हैं। यह काम सिर्फ 2-3 साल तक करें। छोटो-छोटे संगठन बनाएं और संकल्प लें कि हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय चीजों को महत्व देंगे। देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनें और सम्मान के साथ जीवनयापन करें यह हमारी जरूरत है। जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम ने प्रभावित किया जम्मू कश्मीर के हिमायत प्रोग्राम ने मेरा ध्यान खींचा। यह कौशल विकास और रोजगार से जुड़ा है। इसमें 35 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। इसमें वे शामिल होते हैं जिन्हें बीच में अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में 18 हजार लोगों ने ट्रेनिंग ली। इनमें से 5 हजार लोग तो रोजगार कर रहे हैं और दे रहे हैं। हिमायत लोगों के बीच बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है। इसने कश्मीर के युवाओं के बीच आत्मविश्वास बढ़ाया और उनका आगे का मार्ग प्रशस्त किया। आपने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजा है। उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोकसभा ने 114त्न काम किया। राज्यसभा ने 95त्न काम किया। सभी सांसद इसके लिए अभिनंदन के हकदार हैं। जिनको आपने चुनकर भेजा है उन्होंने 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

पीएम मोदी बोले- देशहित के लिए लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी '100 साल एसोचैम (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया)' में शिरकत करने पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एसोचैम ने आज एक अहम पड़ाव पार किया है। 100 वर्ष का अनुभव बहुत बड़ी पूंजी होता है। मैं एसोचैम के सभी सदस्यों को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो। हर राज्य में अलग अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले। हम जीएसटी लाए। व्यापार जगत से जो भी फीडबैक मिला, हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते रहे। उसमें जरूरी परिवर्तन करते रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के लिए काम करने में काफी गुस्सा झेलना पड़ता है, कई लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ती है इसके अलावा कई आरोपों से गुजरना पड़ता है। भांति-भांति के आरोपों से गुजरना पड़ता है लेकिन ऐसाा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि देश के लिए करना है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि 70 साल की आदत को बदलने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात अचानक नहीं आई है। बीते पांच साल में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि ऐसे लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित लोगों को बधाई देता हूं। मैं हर किसी को 2020 के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अपने सभी लक्ष्यों का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में, देश ने खुद को एक बड़े पैमाने पर मजबूत किया है और इस प्रकार, हम पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पांच साल पहले, हमारी अर्थव्यवस्था विनाश की ओर चल रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने इसे बदल दिया है और अनुशासन और सकारात्मकता लाई है।पीएम मोदी ने कहा कि जब तक पूरा देश मिलकर लक्ष्य प्राप्त नहीं करता, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जिम्मेदारी में सक्रियता नहीं लाता तो वो एक सरकारी कार्यक्रम बन जाता है। उन्होंने कहा कि पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जब मैंने सार्वजनिक रूप से कहा तो मुझे पता था कि सुगबुगाहट शुरु हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाएगा कि भारत ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सभी समूह पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा तो करते हैं।प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल को जनसामान्य से जोड़ना ही चाहिए और मेरा यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज देश में वो सरकार है जो किसान की भी

सुनती है, मजदूर की भी सुनती है, व्यापारी की भी सुनती है और उद्योग जगत की भी सुनती है । उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है और उनके सुझावों पर संवेदनशीलता से काम करती है।

पीएम ने कहा कि कंपनी एक्ट में सैकड़ों ऐसे प्रावधान थे, जिसमें छोटी-छोटी गलतियों के लिए क्रिमिनल एक्शन की बात थी। हमारी सरकार ने इसमें से अनेक प्रावधानों को क्रिमिनल एक्शन से मुक्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम करने, उसकी प्रक्रिया को आसान करने को लेकर भी बरसों से देश में तमाम चर्चाएं होती थी। देश में जितना कॉर्पोरेट टैक्स आज है, 100 साल के इतिहास में इतना कम टैक्स कभी नहीं रहा, ये काम भी हमारी सरकार ने किया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मजदूरों को लेकर बदलाव की बातें भी बहुत वर्षों से देश में चलती रही हैं। कुछ लोग ये भी मानते थे कि इस क्षेत्र में कुछ न करना ही मजदूर वर्ग के हित में है। यानि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो, जैसे चलता रहा है, वैसे ही आगे भी चलेगा। लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं मानती है।पीएम मोदी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए, उद्योग जगत के लिए किए जा रहे हर फैसले पर सवाल उठाना ही अब कुछ लोगों का राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से अब 13 बैंक मुनाफे में वापस आ चुके हैं। छह बैंक पीसीए से भी बाहर निकल चुके हैं। हमने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है। बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी वैश्विक पहुंच कायम करने की ओर अग्रसर हैं।पीएम ने कहा कि 2014 से पहले भारत का बैंकिंग क्षेत्र कितना कमजोर था, इसमें कोई संदेह नहीं है। घाटे के लिए छह लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब 70,000 करोड़ रुपये और 2.36 लाख करोड़ रुपये सरकार द्वारा बैंकों को उपलब्ध कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विफलताओं को अपराध नहीं माना जा सकता है। देश कभी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संस्कृति विकसित नहीं कर पाएगा अगर वह ऐसा सोचता है। दुनिया ऐसे लोगों द्वारा चलाई जाती है जिनके पास जोखिम लेने की क्षमता अधिक होती है। पीएम मोदी ने कहा कि जब 2014 से पहले के वर्षों में अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी, उस समय अर्थव्यवस्था को संभालने वाले लोग किस तरह तमाशा देख रहे थे, ये देश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि तब अखबारों में किस तरह की बात होती थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख कैसी थी, इसे आप भली-भांति जानते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज एसोचैम के इस मंच से देश की बैंकिंग से जुड़े लोगों को और कॉरपोरेट जगत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब पुरानी कमजोरियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसलिए खुलकर फैसले लें, खुलकर निवेश करें, खुलकर खर्च करें।

प्रियंका गांधी ने साधा सरकार पर निशाना, कहा

कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं होगा एनआरसी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और एनआरसी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी की योगी आदि?यनाथ सरकार और यूपी पुलिस पर ज?मकर हमला बोला। उन?होंने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस और प्रशासन सीएम के बदला लेने के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में राज्य में सीएए और एनआरसी के दौरान यूपी पुलिस के गैरकानूनी आचरण की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैध नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है एनआरसी। एनआरसी से वैध प्रमाण पत्र का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी को लागू करने का। वैसे भी कांग्रेस के सभी सीएम ने कहा है कि एनआरसी उनके राज्यों में लागू नहीं होगा। दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। इसलिए यह लागू हो ही नहीं सकता, जनता इसे लागू नहीं होने देगी।

लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है। 77 साल के पूर्व आईपीएस दारापुरी को उनके घर से पकड़ा गया। उनका नाम 48 लोगों की सूची में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम ने बयान दिया था कि वो बदला लेंगे, उसी बयान पर प्रशासन और पुलिस चल रही है।

देश में हिंसा और बदले की जगह नहीं

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि जनता के खिलाफ बदला लिया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री ने योगी के वस्त्र धारण किए हैं। भगवा धारण किया है, यह भगवा आपका नहीं है। यह भगवा हिंदुस्तान की धार्मिक, आध्यात्मकि परंपरा का है। हिंदू धर्म का चिह्न है, उस धर्म को धारण कीजिए। उस धर्म में हिंसा, रंच और बदले की भावना की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कृष्ण भगवान का देश है। भगवान राम करुणा के प्रतीक हैं। शिव जी की बारात में सब नाचते हैं। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला और रंच की जगह नहीं है।

पुलिस-प्रशासन का गैर-कानूनी रवैया

उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से इसकी शिकायत की। पिछले दिनों फैली अराजकता के बाद यूपी सरकार, प्रशासन और पुलिस ऐसे कदम उठा रही है, जिनका कोई कानूनी आधार नहीं है। हमने इसी बारे में राज्यपाल को ज्ञापन सौपा है। इसमें पुलिसिया उत्पीड़न के कई उदाहरण भी दिए हैं।14 पन्नों के ज्ञापन पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हस्ताक्षर किए हैं।

उन्होंने कहा कि पहले स्पष्ट होना चाहिए कि हिंसा किसने की? पहले जांच होनी चाहिए। बगैर जांच के कार्रवाई कैसे हो सकती है। बिना जांच के आप ऐसे ऐक्शन कैसे ले सकते हैं, जो सरकार ले रही है।

सभी को प्रताड़ित करेगा यह कानून

उन्होंने भाजपा की ओर से जागरुकता अभियान शुरू करने के बारे में कहा कि यह जागरूकता अभियान नहीं है, झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सभी ने देखी है। सीएए संविधान के खिलाफ है। इससे सभी को आपत्ति होगी, जो गरीब है, श्रमिक है, आप उससे कागजात मांगेंगे। कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी ने सभी को प्रताड़ित किया, उसी तरह से यह भी कानून प्रताड़ित करेगा। आज तमाम छात्र सड़क पर हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, वह समझते हैं कि क्या हो रहा है।

मेरा सुरक्षा का मुद्दा छोटा है

सीआरपीएफ के बयान पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्याओं के सामने मेरी सुरक्षा का मुद्दा बहुत छोटा है। मेरी सुरक्षा से जनता का लेना-देना नहीं है। इसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम राज्य के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। राज्य सरकार और राज्य पुलिस ने कई कदम उठाए हैं, जो कानूनी नहीं हैं और जिससे अराजकता पैदा हुई है। बता दें कि सीआरपीएफ ने सुरक्षा में कोई चूक की बात न कहते हुए प्रियंका गांधी पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

मोदी शाह पर्दे के पीछे से नफरत फैला रहे, दोनों ने युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने ट्वीट कर कहा- प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। इन्होंने देश के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया। इनके पास देश के युवाओं के सवालों के जवाब नहीं हैं, इसलिए ये पर्दे के पीछे से देश में नफरत फैला रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी और शाह अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और रोजगार की कमी पर देश के युवाओं की नाराजगी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं के सवालों का जवाब न होने पर अब वे देश को बांटने की रणनीति अपना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा- देश को बचाने के लिए हमें हर भारतीय से प्रेम भरा व्यवहार करना होगा। हर भारतीय से प्रेम रखकर ही हम उनकी विभाजनकारी नीतियों को नष्ट कर सकते हैं। कांग्रेस देश भर में नागरिकता कानून के विरोध का समर्थन कर रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को जायज और स्वभाविक बताया है।

कई मोर्चों पर पाक के छक्के छुड़ा चुके हैं सीडीएस रावत

अब और मजबूत होंगी भारतीय सेनाएं

सीडीएस के रूप में केंद्र सरकार ने सैन्य मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। करीब दो दशक से उठ रही मांग को अमली जामा पहनाते हुए बीते 24 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद के गठन को मंजूरी दी थी। हफ्तेभर के भीतर ही जरनल बिपिन रावत को पहला सीडीएस बनाने का एलान भी हो गया। करीब तीन वर्ष सेना प्रमुख के रूप में कमान संभालने और सेना के आक्रामक स्वरूप को धार देने के बाद अब जनरल रावत यह नई जिम्मेदारी निभाएंगे।

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख बन गए हैं। बिपिन रावत की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल बिपिन रावत का की जगह ली। जनरल रावत को भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया गया है। तीन साल के कार्यकाल के बाद वह सेवानिवृत्त हुए। दुनिया भर में युद्ध के स्वरूप में हो रहे बदलाव को देख भारत जैसे विशाल देश के लिए रणनीति में सुधार करना जरूरी हो गया है। सीडीएस इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं का अपना एक विस्तृत आयाम है। किसी भी सैन्य कार्रवाई के दौरान इनकी अलग-अलग जरूरत और भूमिका रहती है। ऐसे में कार्रवाई के दौरान इनके बीच समन्वय में जरा सी चूक से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान हमारे सामने ऐसी ही स्थिति आई थी। युद्ध के बाद गठित के सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सही तालमेल न हो पाने के कारण सक्षम होते हुए भी भारतीय सेना को ज्यादा नुकसान हुआ था। उसी समय एक ऐसे समन्वयक पद के सृजन की सिफारिश की गई थी जो इस कमी को पूरा कर सके। दो दशक के बाद इस दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा सका है। ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, चीन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में भी सीडीएस सरीखा पद है। यहां भी ऑपरेशनल कमांड से इतर समन्वय की जिम्मेदारी सीडीएस या इसके समकक्ष अधिकारी को दी जाती है। यह अधिकारी देश के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में भी भूमिका निभाता है। भारत में भी सीडीएस के लिए लगभग ऐसा ही स्वरूप तय किया गया है। सीडीएस की भूमिका प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार की होगी। परमाणु हथियारों के मामले में भी सीडीएस को सलाहकार की भूमिका दी गई है। सीडीएस के पूरे खांचे को देखा जाए, तो यह मात्र एक पद नहीं है, यह एक ऐसा छत्र है जिसके साये में देश की तीनों सेनाएं पल्लवित होंगी। सीडीएस की दिशा में कदम बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि तीनों सेना प्रमुखों के साथ सीडीएस के अधिकारों में कोई टकराव की स्थिति नहीं बने। इसीलिए सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सीडीएस को तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति नहीं बनाया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले की तरह ही अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। इस पद के सृजन के बड़े मायने हैं। भारत अपनी सैन्य चुनौतियों को लेकर सजग

है। नए दौर की नई रणनीति में देश किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहना चाहता है। यह कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि देश में पहले इतने शक्तिशाली किसी पद के सृजन के बारे में नहीं सोचा गया था। सीडीएस सेनाओं और सरकार के बीच पुल की तरह काम करेगा। इसके अलावा सीडीएस की नियुक्ति से सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ना भी संभव होगा। अभी कई बार ऐसा देखने में आता है कि लगभग एक जैसी जरूरतों के लिए भी तीनों सेनाएं अपने-अपने स्तर पर अलग-अलग प्रक्रिया अपनाती हैं। इससे खर्च भी बढ़ता है और देरी भी होती है। सीडीएस के होने से इस खामी को सुधारा जा सकेगा। तीनों सेनाओं के परिचालन, लॉजिस्टिक्स, प्रशिक्षण, संचार, मरम्मत व रखरखाव जैसे कामों में समन्वय में सीडीएस की भूमिका रहेगी। इसके बाद तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त रूप से खरीद, अधिग्रहण जैसी गतिविधियों को अंजाम देना संभव हो सकेगा। संयुक्त संचालन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ व तर्कसंगत प्रयोग करने के लिए सैन्य कमानों के पुनर्गठन और संयुक्त कमानों के गठन का रास्ता भी खुलेगा। पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत का चयन भी सरकार के इरादों को स्पष्ट करता है। जनरल रावत अपनी आक्रामण रणनीति के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई सर्जिकल स्ट्राइक के मुख्य रणनीतिकार वे ही थे। उस समय वह उप सेनाध्यक्ष थे। सेनाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कश्मीर में सेना को खुला हाथ देकर जनरल रावत ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसका नतीजा रहा कि सेना ने पाक सीमा में घुसे बगैर भी उसके कई शिविर ध्वस्त किए और मुंहतोड़ जवाब दिया। जनरल रावत सैन्य सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों के लिए भी जाने जाते हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर टॉप पर

“ स्वच्छता के मामले में इंदौर ने एक बार फिर बाजी मार ली है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। इंदौर के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात का राजकोट और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर नवी मुंबई है। शहरी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप पुरी ने हर तीन महीने पर जारी होने वाली स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पिछली तिमाही में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर था, लेकिन इस बार तीन पायदान नीचे खिसक कर पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

पिछली तिमाही में पांचवें स्थान पर रहा गुजरात का राजकोट इस बार दूसरा सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। गुजरात का ही वड़ोदरा शहर भी साफ-सफाई के मामले में भोपाल से एक पायदान ऊपर चौथे स्थान पर है। ये सभी ऐसे शहर हैं, जहा की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। पुरी के मुताबिक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता के मामले में छठे स्थान पर अहमदाबाद, सातवें पर नासिक, आठवें पर बृहन्मुंबई, 9वें स्थान पर इलाहाबाद और 10वें पर लखनऊ है। पुरी ने कहा, ''एक लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में झारखंड के जमशेदपुर को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर इस श्रेणी में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। मध्यप्रदेश के खरगौन को तीसरा व उत्तर प्रदेश के लोनी को चौथा स्थान मिला है। पांचवे स्थान पर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है।'' वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दिल्ली का एनडीएमसी क्षेत्र छठां सबसे स्वच्छ इलाका है। पुरी ने कहा कि जिन शहरों की आबादी 25 हजार से एक लाख के बीच है, उन्हें पांच अलग-अलग जोन में बांटा गया है। ये उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण व पश्चिमी जोन हैं। उत्तरी जोन में एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का गजरौला पहले स्थान पर, पंजाब का रूपनगर दूसरे और पंजाब का ही राजपुरा तीसरे स्थान पर है।

पूर्वी जोन में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में छत्तीसगढ़ का भिलाई चरोदा पहले स्थान पर रहा है। यहां दूसरा और तीसरा स्थान भी छत्तीसगढ़ को ही मिला है। दूसरे स्थान पर

लगातार चौथी बार हासिल किया सबसे स्वच्छ शहर का तमगा

चिरमिरी और तीसरे पर बिरगांव है। उत्तर पूर्व जोन में एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान नागालैंड के कोहिमा को, दूसरा असम के तेजपुर और तीसरा स्थान भी असम के बोनगै गांव को मिला है।

दक्षिण जोन में एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान आंध्र प्रदेश के चिराला को, दूसरा कर्नाटक के करवार और तीसरा स्थान तमिलनाडु के नमक्कल को मिला है। पश्चिमी जोन में स्वच्छता के लिए तीनों छोटे शहर महाराष्ट्र से हैं। पहला स्थान तेलेगांव दभाड़े, दूसरा स्थान संगमनेर व तीसरा स्थान बल्लारपुर को मिला है।

चर्चाओं में हैं इंदौर की आदर्श सड़क

इंदौर के पॉश इलाके पलासिया चौराहे से साकेत नगर के बीच बनीं आदर्श सड़क भी आजकल चर्चाओं में हैं. यूरोप की याद दिला रही इस सड़क को बनाने में 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. ये सड़क ऐसी है जिसे देखने दूरदराज से लोग आ रहे हैं. जबकि 15 जनवरी को हेमामालिनी और गौतम गंभीर समेत 20 सांसदों का दल भी इसे देखने पहुंच रहा है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी को इसका उद्घाटन करेंगे और वे भी इस सड़क पर बैठकर भोजन करेंगे.

आस्था पर चोट क्यों ?

“ पाकिस्तान में बीते दिनों सिखों के पवित्र तीर्थ ननकाना साहिब की घेरेबंदी और पथराव की घटना ने न केवल पाकिस्तान और भारत बल्कि पूरी दुनिया के सिखों का ध्यान खींचा। पथराव के पीछे एक सिख लड़की के कथित अपहरण और जबरन धर्मांतरण के बाद शादी का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद संबंधित परिवार ने ननकाना साहिब पर धरना दिया। भीड़ द्वारा पथराव की घटना वहां इसी दौरान हुई। इस प्रकरण ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा को एक बार फिर रेखांकित किया है।

पाकिस्तान सरकार अन्य देशों, खासकर भारत में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को लेकर जितनी चिंता आजकल दिखा रही है, उसे ध्यान में रखते हुए यह घटना और महत्वपूर्ण हो जाती है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोगों की स्थिति पर चिंता जताते हुए एक विडियो ट्वीट किया, जो बांग्लादेश का था। बहरहाल, ननकाना साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक छोटा सा शहर है जिसकी आबादी करीब 80,000 है। जिला मुख्यालय भी यह 2005 में बना है। संख्या और आर्थिक व सामाजिक हैसियत के लिहाज से सिख पाकिस्तान में हाशिये पर हैं। जाहिर है, सिखों के इस धर्मस्थान की यहां के ज्यादातर स्थानीय निवासियों की नजर में कोई खास अहमियत नहीं है। ऐसे में पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वहां आने की इजाजत देकर अचानक इस शहर का दर्जा काफी ऊंचा कर दिया। इसके पीछे इमरान सरकार की सोच चाहे जो भी रही हो, इलाके के आम लोग इस बात को पॉजिटिव ढंग से लें, यह सुनिश्चित करने की कोई ठोस कोशिश वहां शायद ही हो पाई है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथ की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह संभावना कम है कि किसी भी क्षेत्र की ज्यादातर आबादी किसी अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक स्थिति में अचानक आई बेहतरी को सहजता से ले सकेगी। ननकाना साहिब जैसे दूर-दराज इलाके का तो कहना ही क्या। ऐसे में बहुसंख्यक प्रतिक्रिया का इलाज क्या है, सिवाय इसके कि वहां लोगों को अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु बनाया जाए, उन्हें धार्मिक कट्टरता के जाल से मुक्त करने का प्रयास किया जाए। जाहिर है, यह काम पाकिस्तान की सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों को ही करना है। वहां के रौशन ख्याल लोग इसके लिए आगे आ सकते हैं और एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष पड़ोसी देश के रूप में हम उन्हें अपना वैचारिक और नैतिक समर्थन दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। जो

लोग इस संदर्भ में नागरिकता संशोधन कानून का हवाला दे रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे पीड़ित मजबूरी में इधर आएं वह अलग बात है, लेकिन अगर वे हमारे बुलाने पर भारत आते हैं तो उन्हें इज्जत की जिंदगी हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे सभी समुदायों को अपनी लड़ाई अपनी जमीन पर लड़नी होती है और बहुसंख्यकों के साथ मिलकर लड़नी होती है।

महाराष्ट्रः उद्धव कैबिनेट में परिवार को प्राथमिकता आदित्य-अशोक चह्वाण समेत 9 चेहरों ने शपथ ली

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ। इसमें 26 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली। उद्धव कैबिनेट में परिवार को प्राथमिकता मिलती दिखी। आदित्य ठाकरे, अशोक चह्वाण और अजित पवार समेत ऐसे 9 चेहरों ने शपथ ली, जिनके पिता या चाचा पहले से ही सक्रिय राजनीति में बड़े मुकाम पर रहे हैं।

अजित पवार

राकांपा प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं। अजित ने मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया गया। हाल ही में अजित ने चाचा शरद से बगावत करके राकांपा के कुछ विधायकों को साथ लेकर उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि, बाद में अजित ने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राकांपा में शामिल हो गए। अजित बारामती सीट से राकांपा विधायक हैं।

आदित्य ठाकरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य मुंबई की वर्ली सीट से शिवसेना विधायक हैं। उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब मंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र में संभवतः यह पहला मौका है, जब पिता-पुत्र यानी उद्धव और आदित्य एक साथ कैबिनेट के सदस्य हैं। 29 साल के आदित्य उद्धव कैबिनेट के सबसे युवा विधायक भी हैं।

अशोक चाह्वाण

भोकर सीट से कांग्रेस विधायक अशोक चाह्वाण ने उद्धव कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। वे राज्य के पूर्व सीएम शंकरराव चव्हाण के बेटे हैं। अशोक चव्हाण 2008 से 2010 के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल है।

अमित देशमुख

लातूर शहर से विधायक अमित देशमुख राज्य के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के बेटे हैं। अमित

पहले महाराष्ट्र सरकार में राज्यमंत्री रह चुके हैं। वे 2009 से लगातार लातूर शहर सीट से चुनाव जीत रहे हैं।

अदिति तटकरे

राकांपा सांसद सुनील तटकरे की बेटी और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिति तटकरे ने राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे उद्धव कैबिनेट में आदित्य के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की मंत्री बनी हैं। अदिति के पिता सुनील तटकरे पूर्व में सिंचाई मंत्री रह चुके हैं। उन्हें राकांपा के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता है।

विश्वजीत कदम

पूर्व कांग्रेसी मंत्री पतंगराव कदम के बेटे विश्वजीत कदम भी राज्यमंत्री बने हैं। वे पलसू कडेगांव सीट से कांग्रेस विधायक हैं। 39 साल के विश्वजीत कदम वर्तमान में वे महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं।

शंकरराव गड़ाख

क्रांतिकारी शेतकारी पक्ष के नेता शंकरराव गड़ाख को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वे पूर्व राकांपा नेता यशवंत राव गड़ाख के बेटे हैं। वे 2014 तक शरद पवार के साथ थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ अलग गुट बना लिया था।

यशोमति ठाकुर

कांग्रेस के पूर्व विधायक स्वर्गीय भैय्यासाहब ठाकुर की बेटी यशोमति ठाकुर (कांग्रेस) ने भी मंत्रिपद की शपथ ली। तिवसा से विधाक यशोमति राज्य कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं। वे मेघालय और कर्नाटक में चुनाव प्रभारी भी रही हैं। वे विदर्भ के तिवसा से विधायक हैं।

वर्षा गायकवाड़

दलित नेता एकनाथ गायकवाड़ की बेटी वर्षा गायकवाड़ (कांग्रेस) मुंबई की धारावी से 4 बार से विधायक हैं। 44 साल की वर्षा गायकवाड़ ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। वे राज्य में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं।

दिल्ली में एक बार फिर आप की आंधी में उड़ सकती हैं बीजेपी, कांग्रेस

दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी को जहां 2015 की प्रचंड जीत को दोहराने की उम्मीद है, वहीं बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से आशावादी है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। इस बीच एबीपी न्यूज-सी वोटर के ऑपिनियन पोल में दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत की भविष्यवाणी की गई है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने सोमवार को कर दिया। दिल्ली में आठ फरवरी को वोटिंग होगी और 11 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, इसको लेकर एबीपी न्यूज ने सीवोटर के साथ मिलकर ओपिनियन पोल किया है। सर्वे के अनुसार, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जलवा कायम रह सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार, चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 59 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह एक बार फिर से दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी हो सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार, बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में महज आठ सीटों के मिलने का ही अनुमान है। पिछले चुनाव में बीजेपी को तीन सीटें मिली थीं। वहीं, पोल में कांग्रेस को भी तीन सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इस तरह कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले तीन सीटों का फायदा हो सकता है। पिछली बार कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता था।

वहीं, आम आदमी पार्टी को 53.30त्न वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी के खाते में 25.90त्न वोट आ सकते हैं। वहीं, कांग्रेस को 4.7त्न वोट मिलने का अनुमान जताया गया है।

दिल्ली की 70 सीटों पर 8 फरवरी को होंगे चुनाव, 11 फरवरी को आएंगे

दिल्ली में 1.46 करोड़ से अधिक मतदाता

दिल्ली में आठ फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 1.46 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। सोमवार को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से यह जानकारी मिली। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रणबीर सिंह ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची में यहां कुल 1,46,92,136 मतदाता हैं, जिनमें 80,55,686 पुरूष और 66,35,635 लाख महिलाएं तथा 815 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

झारखंडः राज्यों में भाजपा की जादुई छड़ी बेअसर

एक साल में गंवाया 5वां राज्य

झारखंड मुक्ति मोर्चा(झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सोरेन के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम व रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय जनता

दल (राजद) नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। एक के बाद एक बड़ी चुनावी सफलता है हासिल कर चुनावी चाणक्य का खिताब पाने वाले अमित शाह की जादुई छड़ी मानों कहीं खो गई है। खासतौर पर विधानसभा चुनावों में। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार इसी कड़ी का एक हिस्सा है। झारखंड में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी प्रमुख भाजपा नेताओं की रैलियां आयोजित कीं। अंतिम दो चरणों में प्रधानमंत्री ने जमकर प्रचार किया और अपने नाम पर वोट मांगे।

पन्ना प्रमुख, बूथ मैनेजमेंट से लेकर सोशल मीडिया तक का सहारा लिया गया। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकारों की उपलब्धियों का जमकर प्रचार किया गया। इसके बावजूद पिछली बार के मुकाबले पार्टी 12 सीटें कम जीती और बहुमत से दूर रह गई। झारखंड वह राज्य है जहां अभी 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में उसे 14 में से 12 सीटों पर विजय मिली थी। अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों को 40 से 50 प्रतिशत तक वोट मिले। फिर आखिर कमी कहां रह गई कि उसके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ही जीत से वंचित रह गए।

क्या भाजपा अति आत्मविश्वास का शिकार हुई? क्या आजसू के साथ गठबंधन न करना उसे महंगा पड़ा? या एक गैर आदिवासी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग उल्टा पड़ा? या फिर विधायकों और राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ी? या झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन ज्यादा मजबूत साबित हुआ? या फिर पिछले 40 वर्षों से पार्टी के साथ रहे वरिष्ठ नेता सरयू राय का टिकट काटना उसे भारी पड़ा? अगले एक-डेढ़ महीने के अंदर होने वाले दिल्ली चुनाव और उसके बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उसे इन सवालों के जवाब ढूंढ लेने पड़ेंगे। आखिर इसी रणनीति के सहारे शाह ने 2014 में भाजपा को 282 सीटें दिलाई और पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें। इनके अलावा 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2017 में उन्होंने भाजपा के गठबंधन को 325 सीटें दिलाईं। लेकिन उसके बाद शाह के चुनावी कौशल के बावजूद अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के अलावा भाजपा एक के बाद एक सभी विधानसभा चुनाव हारती चली गई। झारखंड के नतीजे इस मायने में आश्चर्यजनक नहीं कहे जा सकते।

दूसरों के दम पर राज

इस दौरान यदि पार्टी ने बिहार, कर्नाटक, हरियाणा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, गोवा आदि राज्यों में सरकार बनाई तो जोड़ तोड़ के दम पर।

मौके पर मारा चौका

बिहार में नीतीश कुमार ने यदि राष्ट्रीय जनता दल का साथ न छोड़ा होता तो भाजपा की सरकार नहीं बनती। इसी तरह कर्नाटक में भाजपा को जनता दल सेकुलर और कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए सरकार बनाने

का मौका मिला। हरियाणा में भी पार्टी बहुमत से दूर रह गई लेकिन दुष्यंत चौटाला के समर्थन से उसने सरकार बनाई।

भाजपा ने एक साल में गंवाया 5वां राज्य

लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र के बाद झारखंड की सत्ता भी गंवा दी है। हरियाणा में किसी प्रकार सत्ता बचाने में कामयाब रही भाजपा को बीते एक साल में 5 राज्यों (इससे पहले मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान) की सत्ता गंवानी पड़ी है। संदेश साफ है। पार्टी राज्यों में हार का मिथक तोडने में कामयाब नहीं हो पा रही। वह भी तब जब पार्टी और मोदी सरकार एक के बाद एक राष्ट्रवादी एजेंडे को अमली जामा पहना रही है। जाहिर है कि झारखंड के निराशाजनक नतीजे के बाद भाजपा में चिंता है।

दिलचस्प तथ्य यह है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी जिन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव हारी, उन्हीं राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। इसके बाद जिन दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में पार्टी हारी और हरियाणा में किसी तरह सत्ता बचाने में कामयाब रही, उन राज्यों में पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। वर्तमान झारखंड का ही उदाहरण लें तो पार्टी का वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 17 फीसदी लुढ़क गया।

नाकाम साबित हो रहे क्षत्रप

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद से ही भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों में भविष्य की राजनीति के लिए नया नेतृत्व उभारने पर जोर दिया। हालांकि परिणाम बताते हैं कि ऐसा कोई भी चेहरा अपने सूबे में अपनी मजबूत छवि बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। वह भी तब जब पार्टी आलाकमान ने इन्हें कामकाज के मामले में न सिर्फ लगातार फ्री हैंड दिया, बल्कि विरोधी धड़े की आवाज को रत्ती भर तवज्जे नहीं दी। महाराष्ट्र में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में वर्तमान सीएम मनोहर लाल और अब झारखंड में सीएम रघुवर दास कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए।

हेमंत सोरेन बने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री

झारखंड मुक्ति मोर्चा(झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में सोरेन के साथ कांग्रेस नेता आलमगीर आलम व रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं।

समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, भाकपा महासचिव डी. राजा, द्रमुक प्रमुख एम.के. स्टालिन, आम आदमी पाटी के सांसद संजय सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मंच पर मौजूद रहे। इस मौके पर सोरेन का परिवार भी समारोह में पहुंचा। हेमंत के पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन भी मंच पर मौजूद रहे। उनकी पत्नी समेत परिवार के बाकी सदस्य भी समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले हेमंत ने जुलाई, 2013 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजुर्न मुंडा सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सोरेन इससे पहले 2013 में राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने और दिसंबर 2014 तक इस पद पर रहे। वर्ष 2014 में राज्य में भाजपा की सरकार बन गई, झारखंड को रघुवर दास के रूप में गैर-आदिवासी मुख्यमंत्री मिला और हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष बने। शपथ ग्रहण समारोह के पूर्व हेमंत अपने पिता के आवास पहुंचे और माता-पिता से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वह अपने पिता शिबू को अपनी ही गाड़ी में समारोह स्थल तक साथ ले गए।

हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंडी संस्कृति पर जोर दिया गया। मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का मंच झारखंड की कोहबर कला के साथ ही झारखंडी कला-संस्कृति को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। मंच को पूरी तरह कोहबर कला (पेंटिंग) से सजाई गया। झारखंड की 81 विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की

अगुवाई में झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने 47 सीटें हासिल की थीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट मिली, बाबूलाल मरांडी की झाविमो को 3 सीटें और आजसू को 2 सीटें हासिल हुईं। भाजपा को 25 सीटें मिलीं।

पुष्पांजली टुडे पत्रिका को जन-जन तक पहुंचाना है

श्री श्री 1008 दंदरौआ महाराज जी को
पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

श्री संतकृपाल महाराज जी को
पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

मप्र के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी को
पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को
पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

ग्वालियर आरटीओ एम पी सिंह जी को
पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

रविंद्र मानिकपुरी सहायक आबकारी आयुक्त
ग्वालियर को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए

ग्वालियर नगर निगम अपर आयुक्त नरोत्तम भार्गव जी
को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए

भिण्ड डीएसपी सतीश दुबे जी को पुष्पांजली टुडे
पत्रिका भेंट करते हुए

पुष्पांजली टुडे पत्रिका को जन-जन तक पहुंचाना है

ग्रीन वुड स्कूल की संचालिका किरन भदौरिया जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

उप्र झांसी मंडल के रेलवे अधिकारी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

गोले का मंदिर थाना प्रभारी हीरा सिंह चौहान जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

गुना-शिवपुरी सांसद केपी यादव जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

जिला भिण्ड स्थित उमरी थाना प्रभारी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

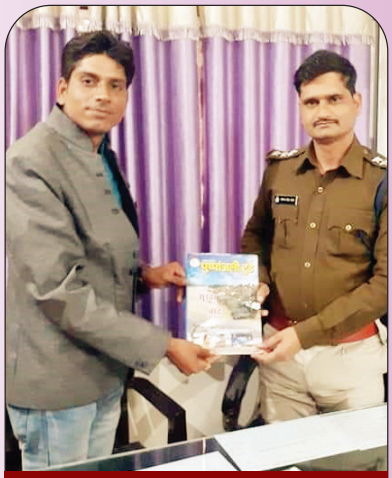

दतिया सिटी कोतवाली प्रभारी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

पड़ाव थाना प्रभारी ज्ञानेन्द्र सिंह जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

योगेन्द्र जी महन्त प्रदेशाध्यक्ष विश्व ब्राह्मण संघ एवं पूर्व राज्य मंत्री जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए

गोहद थाना प्रभारी जी को पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए

पोरसा थाना प्रभारीको पुष्पांजली टुडे पत्रिका भेंट करते हुए।

कमलनाथ सरकार का एक साल

पहली सालगिरह पर पूर्व डॉ मनमोहन सिंह ने जारी किया कमलनाथ सरकार का

विजन टू डिलेवरी रोड मैप

“

कमलनाथ सरकार का एक साल पूरा हो गया. सालगिरह पर भोपाल में कार्यक्रम हुआ जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह और सीएम कमलनाथ ने विजन टू डिलेवरी रोड मैप जारी किया. इसमें कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों और अगले 4 चार में प्रदेश के विकास के लिए की प्लानिंग का ज़िक्र है. इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा-बीते एक साल में खाली ख़ज़ाने के साथ विकास कार्य करना चुनौती भरा रहा. कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर भोपाल स्थित पुरानी विधानसभा भवन मिंटो हॉल में सरकारी कार्यक्रम हुआ. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह मुख्य अतिथि थे. समारोह में विजन टू डिलेवरी रोड मैप 2020-2025 जारी किया गया. इसमें विकास का रोडमैप है. कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को बताती एक फिल्म भी दिखायी गयी.

चुनौती भरा सफर

इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा,प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना सरकार के लिए चुनौती भरा रहा.हमारी सरकार को खाली ख़ज़ाना मिला था. ख़ज़ाना भरना और योजनाओं पर अमलबड़ी चुनौती साबित हुआ.पुरानी सरकार ने बजट में पैसे का इंतज़ाम किए बिना घोषणाएं कीं. हमने उस चुनौती को स्वीकार किया और पिछली सरकार के बोझ को उठाया और योजनाएं पूरी कीं.

जनता का सर्टिफिकेट चाहिए

सीएम कमलनाथ ने कहा हम घोषणाओं और प्रचार की सरकार नहीं हैं. जनता का सर्टिफिकेट पाना ही सरकार का लक्ष्य है. हमारी सरकार ने 365 दिन में 365 वचन पूरे किए.कृषि और किसानों की हालत सुधारने के लिए कर्ज़माफ़ी का फैसला किया गया. एक साल में पात्र किसानों का कर्ज़ माफ़ किया.50 हजार तक का कर्ज पहले चरण में पूरा किया.

दूसरे चरण का ऐलान

कमलनाथ ने किसानों की कर्जमाफी का दूसरा चरण आज से शुरू करने का एलान किया. उन्होंने कहा एक लाख तक का कर्ज़ माफ किया जाएगा. सरकार के पास हर किसान का रिकॉर्ड मौजूद है. उन्होंने कहा100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने के वादे पर हमने अमल किया. तेंदूपत्ता मजदूरों को 2500 रुपए देने का फैसला किया. पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण, विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने का फैसला किया. रेत खनन की नई नीति लागू की और कई नियम सरल बनाए.

सीएम कमलनाथ के विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णय

मध्यप्रदेश के लोकोन्मुखी प्रशासनिक इतिहास में निःसंदेह, वर्ष 2019 विवेकपूर्ण और साहसिक निर्णयों तथा सार्थक आयोजनों के वर्ष के रूप में याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में श्री कमल नाथ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने का अपना पहला साहसिक निर्णय लिया। नतीजतन, लगभग 20 लाख किसानों को अब तक राहत मिली और बाकी को राहत मिलना जारी है। यह एक बहुप्रतीक्षित निर्णय था। किसानों द्वारा की गई आत्म-हत्याओं के लिए मुख्य रूप से ऋणग्रस्तता और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की विफलता जैसे कारण बताए गए थे। प्रासंगिक राजस्व कानूनों के तहत किसानों को सामान्य प्रावधानों से अलग हटकर राहत की जरूरत महसूस की जा रही थी।सरकार ने तुरंत कृषि ऋणों को माफ करने का अपना पहला आदेश जारी कर अपने पहले वादे का सम्मान किया। खाली हो चुके सरकारी खजाने को देखते हुए निर्णय पर प्रारंभिक रूप से संदेह व्यक्त किया गया। यह प्रभावशाली शुरुआत थी। इसके बाद विवेकपूर्ण फैसलों की एक श्रृंखला-सी बन गई। शासन को मज़बूती देना और नई चुनौतियों का सामना कर समाधान निकालना आवश्यक था। वर्ष के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि पहले की सरकार की घोषणाओं और प्रयासों के लिए बजटीय प्रावधान ही नहीं किए गए थे। जनजातीय बहुल क्षेत्रों में गैरकानूनी रूप से साहूकारी का प्रचलन हमेशा एक समस्या रही है। छोटी-छोटी रकम की जरूरतों के लिए जनजातीय परिवारों को अनौपचारिक रूप से काम कर रहे साहूकारों पर निर्भर रहना होता है और वे तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई वर्षों तक कर्ज़ से दबे रहते हैं। कर्ज में डूबे ऐसे आदिवासी परिवारों के पक्ष में दूसरे साहसिक निर्णय ने काफी हलचल पैदा की। जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा ब्याज दर पर उधार देने की साहूकारी प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई। परिणामस्वरूप, कई आदिवासी परिवार साहूकारों की ऋणग्रस्तता के चक्र से बाहर आ गए।

अर्थ-व्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे फैसले और रणनीतिक प्रयास देखे गए। मध्यप्रदेश को आदिवासी कलाओं की विरासत के संरक्षण का विशेषाधिकार पहले

ही मिला है। जाने-माने कलाकार स्वर्गीय जनगढ़ सिंह श्याम ने मध्यप्रदेश को दुनिया भर में आदिवासी कला के केन्द्र के रूप में पहचान दिलाई थी। हाल ही में भज्जू सिंह श्याम को गोंड चित्रों की परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गोंड चित्रकला की विशिष्ट परंपरा और शैली को आगे बढ़ाने के लिए कई गोंड जनजातीय चित्रकार स्व-प्रेरणा से आगे आ रहे हैं। गोंडी बोली में प्राथमिक कक्षाओं के लिए पठन सामग्री को गोंड जनजाति समुदाय के छात्रों के लिए तैयार करने के निर्णय को सराहना मिली। दुनिया भर में देशज लोगों की लुप्तप्राय हो रही बोलियों और भाषाओं के मद्देनजर यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषाई पहचान के संकट के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि इनकी रक्षा तभी हो सकती है, जब इन्हें ज्यादा से ज्यादा बोला और पढ़ा जाए। इसी तरह, 2019 को गोंड कला वर्ष घोषित किया गया।

बिना देखभाल के घूम रहे गो-वंशीय पशुओं के लिए गौ-शाला निर्माण के राज्य सरकार के एक और महत्वपूर्ण निर्णय ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया है। गहन समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अनाथ पशुओं के लिए कोई सरकारी स्वामित्व वाली या संचालित गौ-शाला नहीं है। ऐसे पशु यातायात के लिए खतरा बन रहे हैं, साथ ही खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस निर्णय के तुरंत बाद, कई लोग गौ-शाला बनाने के लिए भूमि और सामग्री दान करने की सरकार की घोषणा के समर्थन में सामने आए। कुछ औद्योगिक घराने इस उद्देश्य के लिए अपने सीएसआर फंड देने की पेशकश कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिड़ला ने उच्च तकनीकी युक्त गौ-शालाओं के निर्माण की घोषणा की। इस वर्ष अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से गरीब तबके के लोगों के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण करके लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले वास्तव में आम आदमी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मिलावट-मुक्त भोजन का उपयोग करने के बारे में दुनिया में लोगों में चेतना बढ़ रही है। दुनिया भर में सरकारें लोक स्वास्थ्य के प्रति चेतना और साक्षरता बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। मध्यप्रदेश जैसे राज्य लोक स्वास्थ्य को खतरे में डालकर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की अनुमति के लिए कभी तैयार नहीं हो सकते। हाल ही में, मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक सतत अभियान चलाने का दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय लिया गया। इस अभियान को खुले मन से लोगों का समर्थन मिल रहा है इसी वर्ष रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर गाइड-लाइन दर को 20 प्रतिशत तक कम करने की रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई। सबसे उत्साहजनक उपलब्धि मध्यप्रदेश को तब मिली, जब टाइगर राज्य का दर्जा दोबारा हासिल हुआ। इसका श्रेय निःसंदेह रणनीतिक वन्य-जीव संरक्षण प्रयासों और राष्ट्रीय उद्यानों के कुशल प्रबंधन को जाता है। इंदौर में मैग्नीफिसेन्ट मध्यप्रदेश, छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल और भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेले जैसे आयोजनों की काफी चर्चा रही।

देश में पहली बार राजस्थान में लागू होगा जवाबदेही कानून

देश में पहली बार राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जवाबदेही कानून लागू करेगी। कानून बनकर तैयार है, नए साल मे इसे लागू कर दिया जाएगा। जवाबदेही कानून के दायरे में 25 विभागों की 220 सेवाओं को शामिल किया गया है। गहलोत सरकार जवाबदेही कानून के माध्यम से सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने और आम लोगों को राहत देने का प्रयास कर रही है। एक साल पहले सत्ता संभालते ही सीएम गहलोत ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदार तय करने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने देश में पहली बार प्रदेश में जवाबदेही कानून बनाने की बात कही थी।कानून का मसौदा तैयार करने के लिए गहलोत ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने गहलोत की मंशा के अनुसार कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। अब नए साल में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस कानून पर मुहर लगाई जाएगी। इस कानून में पंचायती राज, जलदाय, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, कृषि, कृषि विपणन, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, चिकित्सा, देवस्थान, ग्रामीण विकास, वन, रोड़वेज आदि विभागों और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया गया है। राज्य के स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल का दावा है कि देश में पहली बार राजस्थान में इस तरह का कानून अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवाओं की गारंटी और अधिकारियों की जवाबदेही को इस कानून में शामिल किया गया है। जवाबदेही कानून के तहत प्रदेश में प्रत्येक पंचायत समिति एवं नगर पालिका स्तर पर सुनवाई होगी। इसके लिए पंचायत समिति एवं नगर पालिक स्तर पर सूचना और सहयोग केंद्र स्थापित होंगे। उपखंड अधिकारी की अगुवाई में एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी आम लोगों की पानी, बिजली, शौचालय, सड़क, राशन, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति-प्रमाण-पत्र, विधवा पेंशन, वाहन चालक का लाइसेंस सहित आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई करेगी।

सुनवाई के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे शिकायतों का निस्तारण करें। सुनवाई के बाद शिकायत का निस्तारण यदि एक माह में नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक माह बाद शिकायत पर जिला सतर्कता समिति सुनवाई करेगी। जिला स्तरीय समिति में मामलों का निस्तारण तय समय पर करना होगा, यदि इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी टालमटोल करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। कमेटी में सेवानिवृत आइएएस अधिकारी रामलुभाया,सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, प्रो.देवेंद्र कोठारी के साथ अलवर एवं उदयपुर जिलों के कलेक्टरों को शामिल किया गया था। सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा राय के सुझाव के अनुसार

सीएम गहलोत ने कमेटी को कानून के दायरे में लाए जाने वाले विभागों और सेवाओं को जोड़ने के लिए कहा था। कमेटी ने देश और प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, वकीलों, प्रोफेसर्स और आम लोगों की राय लेकर कानून का मसौदा तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में देश में पहली बार सूचना का अधिकार देश में सबसे पहले राजस्थान में ही लागू किया था।

सहकारिता आंदोलन को गतिशील बनाया जाएगा : गोविंद सिंह

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को बहुत क्षति पहुँची है। उन्होंने कहा कि आगामी एक-डेढ़ वर्ष में सहकारिता आंदोलन को तेज किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ के चुनाव भी शीघ्र कराये जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने की। अपेक्स बैंक में आयोजित बैठक में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये उसके कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण, शासकीय आवास निर्माण, शहरी विकास के निर्माण कार्य और गृह निर्माण समितियों की खाली पड़ी जमीनों पर विकास कार्य राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से कराये जाएंगे। डॉ. सिंह ने राज्य आवास संघ पर बाकी जीवन बीमा निगम की ऋण राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ऋण

चुकाने के लिये अपनाई गई वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया मध्यप्रदेश में भी अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में जीवन बीमा निगम से चर्चा कर ऋण प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों में सहकारी आवास संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये संघों को नये प्रोजेक्ट प्राप्त करने होंगे। उन्होंने कहा कि अब आवास संघ को अपनी ऋण देने की एजेंसी का स्वरूप त्यागना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक एजेंसियाँ काम करने लगी हैं। श्री शर्मा ने सहकारी आंदोलन में डॉ. गोविंद सिंह के योगदान की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी डॉ. सिंह के अनुभवों का लाभ मिलेगा। बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ पर जीवन बीमा निगम का कुल 337 करोड़ रुपये ऋण बकाया है। इसमें मूल केवल 79 करोड़ रुपये है। जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश इस मूल की ऋण राशि का एक साथ भुगतान करने के लिये तैयार है। इसके लिये जीवन बीमा निगम से वन टाइम सेलटमेंट की कार्यवाही की जा रही है।

होनहार बेटियों ने मिटाया चंबल पर लगा दाग़, दिलायी नयी पहचान

बीहड़,डकैत और कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम चंबल इलाके की बेटियां अब इलाके को नयी पहचान दे रही हैं. इस इलाके पर लगे दाग़ को मिटा रही हैं. वो समाज को जगा भी रही हैं और कानून अपने हाथ में लेने वालों को सबक सिखाने के लिए भी तैयार हैं. कुख्यात चंबल अब वो पुराना चंबल नहीं रहा.कुछ ऐसी ही बेटियों के बारे में इस रिपोर्ट में जानिए. बात करते हैं भिंड ज़िले के एक छोटे और गुमनाम से गांव बंथरी की.ये वो गांव है जहां की 8 बेटियां अब मध्य प्रदेश पुलिस में हैं.ये पिछले तीन साल के दौरान पुलिस में आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के पद पर भर्ती हुई हैं.

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने त्रिवेणी राजावत को सम्मानित किया

बदल दी तस्वीर

मध्य प्रदेश का भिंड ज़िला भ्रूण हत्या के लिए लंबे समय तक बदनाम रहा.लड़का-लड़की के अनुपात का अंतर भी यहां सबसे ज़्यादा रहा. यानि लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम रही.लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल रही है.जहां कभी लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता था वहीं अब एक ही गांव की आठ बेटियों ने पुलिस सेवा में भर्ती होकर अपने गांव के साथ साथ ही ज़िले का भी नाम रौशन किया.

एक गांव की 8 बेटियां

शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिसमें एक ही गांव से इतनी संख्या में बेटियां देश सेवा-जन सेवा कर रही हों.इन बेटियों की हौसला अफजाई करने के साथ ही समाज के अन्य तबकों के लोगों को भी भ्रूण हत्या रोकने एवं बेटियों को आगे बढ़ने का संदेश देने के लिए मिहोना नगर परिषद ने हाल ही में इनका सम्मान किया. प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह खुद यहां आए और बेटियों को इन बेटियों को प्रशस्ति पत्र दिए.

बंथरी गांव की त्रिवेणी राजावत, कीर्ति राजावत, शिवानी राजावत अब सब इंस्पेक्टर हैं. इनके साथ गीता राजावत,शिवानी जादौन और रुचि राजावत सहित दो अन्य आरक्षक हैं. मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा, बेटियों की शिक्षा और उनके सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.बंथरी गांव के विकास के लिए उन्होंने दस लाख रुपए भी मंजूर किए.

आशा दीदी

अब बात मुरैना की एक बेटी जिन्हें लोग आशा दीदी कहने लगे हैं. एक बागी की पोती और बेटी आशा सिकरवार ने कोख़ में क़त्ल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और बदलाव लाकर ही सांस ली. उन्होंने लगभग 10 साल तक चंबल के बीहड़ में घर-घर जाकर कोख में बेटियों की हत्या करने के ख़िलाफ लोगों को समझाया. बेटियों का महत्व समझाया. उन्हें लोगों ने नकारा, धमकाया लेकिन उनका तो नाम ही आशा है. इसलिए उन्होंने बेटियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव की आशा नहीं छोड़ी.

पुरस्कार और सराहना

पेशे से वकील आशा सिकरवार ने अपने करियर को एक तरफ छोड़ा और कोख में कत्ल करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी. इसके बाद वर्ष 2005 में लिंगानुपात में 1000 के मुकाबले जहां 635 बेटियां थीं वो 2015 - 16 में बढ़कर 850 के करीब पहुंच गई. आशा दीदी के काम को देशभर में सराहा गया. उन्हें कई पुरस्कार मिले.

दादा-पापा थे बागी

आशा सिकरवार के दादा सिंधिया रियासत में बागी थे. बागी डूंगर बटरी के नाम से आशा के दादा को लोग जानते थे. उनके फैसले के आगे कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था. वो साहूकारों को लूट कर वो पैसा गरीबों में बांट देते थे. आशा के पिता परशुराम भी बागी हुए. उन्होंने भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर गरीबों की बेटियों की शादी और सुरक्षा दिलवायी.

पुलिस में भर्ती होकर जिले का नाम रोशन करने वाली क्षेत्र की होनहार बेटियों ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से मुलाकात की।

कानून के साथ आशा

आशा जब छोटी थीं तो दादा की कहानी और पिता के काम देखे. लेकिन उन्होंने तय किया कि कानून तोड़कर नहीं बल्कि कानून के साथ मिलकर गरीबों और बेबसों की मदद करेंगी. यही उन्होंने किया भी.

आम लोगों से बेहतर तालमेल स्थापित करना एक सफल पुलिस अधिकारी की पहचान हैः आईपीएस भसीन

रिपोर्टः रहीस खॉन ग्वालियर

नाम- नवनीत भसीन

माताजी-श्रीमति किरन भसीन

पिताजी-श्री सूरज प्रकाश भसीन

जीवन संगिनी- श्रीमति शुभांगी भसीन

जन्म -15.02.1979

जन्म स्थान-शिवपुरी म0प्र0

बैच-2009 (IPS)

वर्तमान पदस्थासपना- पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। ग्वालियर जैसे चुनौतीपूर्ण जिले के पुलिस

अधीक्षक नवनीत भसीन एक होनहार और काबिल पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। जबसे उन्होने ग्वालियर पुलिस कप्तान का कार्यभार संभाला है तब से ग्वालियर जैसे चुनौतीपूर्ण जिले में अपराध पूर्व की तुलना में कम हो गया है। हमारे ग्वालियर संवाददाता रहीश खान ने नवनीत भसीन से मुलाकात कर जिले के हालातों पर और आमजनों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुऐ तमाम मुद्दों पर पुलिस कप्तान से चर्चा की।

जिले में अमन शांति का माहौल बना रहे इस हेतु आपकी क्या कार्यप्रणाली होगी?

निसंदेह आपका सवाल बिलकुल सही है किंतु जब से मैंने पदभार ग्रहण किया है मैं समझता हूं कि मुझे थोड़ा समय जिले की भौगोलिक स्थिति को समझने और जिले में पुलिस के काम करने के तरीके को और भी बेहतर बनाने में थोड़ा वक्त जरूर लगा। लेकिन में आपकी राष्ट्रीय समाचार पत्रिका के माध्यम से ग्वालियर जिले की आम जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि जिले का हर आदमी भयमुक्त वातावरण में रहेगा और समाज के अंदर अमन और शांति का माहौल बना रहे इस हेतु ग्वालियर पुलिस लगातार काम करेगी।

जिले में जुआ शराब सट्टा जैसी सामाजिक बुराई से ग्वालियर पुलिस किस तरह से निपटेगी इसके साथ ही जिले में अवैध उत्ख नन भी होता है इन सब पर विराम लगे। इस हेतु आपकी क्या रणनीति होगी?

देखिए अवैध उत्खनन जैसे गंभीर मामलों के बारे में मैंने जिलाधीश अनुराग चौधरी से चर्चा कर एक टीम बनाई है। उस टीम के माध्याम से हम लगातार छापामार कार्यावाहियां कर रहे है। इसके साथ ही में जिले की आम जनता से भी अपेक्षा करूंगा कि ऐसे गंभीर अपराध,अवैध परिवहन,उत्खनन अगर किसी भी आम आदमी की नजर में आते है तो वे मेरे पर्सनल नंबर पर या संबंधित पुलिस अधिकारियों के नंबर पर सूचना देकर अपनी जिम्मेदारी निभाऐं। मैं मातना हूं कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस अधूरी है हर बड़े से बड़ा अपराध जनता के सहयोग से समाप्त किया जा सकता है। रहा सवाल जुआ, सट्टा और शराब जैसी सामाजिक बुराई का तो मैं फिर आम लोगों से कहना चाहता हूं कि ग्वालियर पुलिस की कार्यप्रणालियों पर भरोसा रखें निश्चित रूप से इन सामाजिक बुराईयों को समाप्त कर समाज में एक बेहतर वातावरण बनाने हेतु ग्वालियर पुलिस दृढ संकल्पित है।

- एक ही थाने में तीन साल से ज्यादा समय गुजार रहे पुलिसकर्मियों को दूसरे थानों में स्थानांतरित करने हेतु क्यास प्रभारी कदम उठाया गया है?

- देखिए यह मुद्दा काफी अहम है कि ग्वालियर जिले के कई ऐसी थाने है जिनमें कई पुलिसकर्मी 3 से ज्यादा समय गुजार चुके है कई पुलिसकर्मियों को 3 वर्ष का समय होने वाला है। जल्द ही इन्हें एक थाने से दूसरे थाने में स्थांनांतरिक करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

-जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जिलों में पुलिस बल, वाहन, और संसाधन मौजूद नहीं है, ऐसे में क्या, प्रयास आपके स्तर से किये जा सकते है?

- देखिए शासन प्रशासन के स्तर से इस कमी को पूरा करने का प्रयास लगातार जारी है। यह भी सच है जनसंख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन बलों में भी लगातार वृद्धि हुई है, आगे भी शासन प्रशासन के सामने ऐसी समस्याओं को रखा जाएगा ताकि हर जिलों में पर्याप्त बल और संसाधान मौजूद हो।

- मादक पदार्थ की तस्करी होती रहती है, ऐसी शिकायतें और जानकारियां मिलती रहती है, इस पर नियंत्रण कैसे संभव है?

- पुलिस के लिये हर काम संभव है और पुलिस हर अपराध नियंत्रण पर काम कर रही है। पूर्व में भी गालव रिषी की तपोभूमि ग्वालियर में पुलिस ने मादक पदार्थो की तस्करी के विरूद्ध अभियान चलाकर ऐसे कामों में लिप्त आरोपियों पर वैधानिक कार्यवाहियां की है,में आपकी पत्रिका के माध्यम से ग्वालियर की आम जनता को विश्वास दिलाता हूं वर्तमान समय में भी ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही होगी तो वह पुलिस से बच नहीं सकेंगे। हमारा ध्येय ही समाज को अपराध से मुक्तय बनाना है।

राशन उपभोक्ताओं के लिये अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू: तोमर

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि जनवरी 2020 से प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था में प्रदेश के उपभोक्ता देश के 11 राज्यों आन्ध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में भी अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, इन 11 राज्यों के उपभोक्ता मध्यप्रदेश में राशन ले सकेंगे। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना में उपभोक्ता राशन पूर्व निर्धारित मात्रा में पूर्व निर्धारित दर गेहूँ 2 रुपये, चावल 3 रुपये और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम पर प्राप्त कर सकेंगे।

वन स्टेट-वन राशन योजना

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभन्वित करने के लिये अक्टूबर 2019 से प्रदेश में वन स्टेट-वन राशन योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार इस योजना को लागू करने पर अभी सिर्फ विचार कर रही है। श्री तोमर ने बताया कि इस योजना में राशन उपभोक्ता एक शहर अथवा एक वार्ड से दूसरे शहर अथवा दूसरे वार्ड में भी राशन दुकान से निर्धारित मात्रानुसार निर्धारित दर पर राशन ले सकता है।

मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने दी उपलब्धियों और नवाचारों की जानकारी

इस योजना से आज प्रदेश के 117 लाख से अधिक परिवार के साढ़े पाँच करोड़ उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पिछले एक साल में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विकास के विशेष प्रयासों एवं नवाचारों की जानकारी देते हुए कहा कि राशन उपभोक्ताओं का हित संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। इसमें पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर किया जाकर राशन वितरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में वृद्धजन/निश्शक्तजन को दुकान तक राशन लेने आने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति (नामित)के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। पात्र हितग्राहियों को दृग्ड्डष्ट की सुविधा पीओएस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना

मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्य सुरक्षा दाल वितरण योजना लागू की गई है। इसमें चने की वितरण दर 27 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। प्रति सदस्य एक किलो एवं अधिकतम चार किलो प्रति परिवार पात्रता सुनिश्चित की गई है। इस व्यवस्था में हर महीने 117 लाख 47 हजार पात्र परिवारों को 40 हजार 793 मेट्रिक टन आवंटन दिया गया है। दाल का वितरण माह फरवरी से अक्टूबर, 2019 तक किया गया। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा दाल का आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

सर्वसुविधायुक्त बनेगा मीडिया सेन्टर: जनसम्पर्क मंत्री शर्मा

भोपाल। जनसम्पर्क मंत्री श्री पी.सी. शर्मा ने मीडिया सेंटर के निर्माण के संबंध में सुझाव देने के लिए पत्रकारों की बैठक में कहा कि मालवीय नगर, भोपाल में सर्वसुविधायुक्त मीडिया सेन्टर बनाया जायेगा। बैठक में पत्रकारों ने मीडिया सेंटर के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

जनसम्पर्क मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पत्रकारों द्वारा दिये गए सुझावों को प्रोजेक्ट में शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के निर्देशानुसार ही नये पत्रकार भवन (मीडिया सेंटर) के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गयी है। श्री शर्मा ने कहा कि जल्द ही भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जायेगा। प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री संजय कुमार शुक्ला ने कहा कि यह बैठक पत्रकार भवन के निर्माण के संबंध में है। उन्होंने बताया कि पत्रकार भवन के संचालन के संबंध में अलग से सुझाव लिये जायेंगे। आयुक्त जनसम्पर्क श्री पी. नरहरि ने प्रस्तावित पत्रकार भवन (मीडिया सेंटर) की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर आर्किटेक्ट श्री अजय कटारिया ने प्रस्तावित मीडिया सेंटर की डिजाइन के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। संचालक जनसम्पर्क श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एक वर्ष में 5690 करोड़ की 36 लघु सिंचाई योजनाएँ मंजूर

प्रदेश में एक वर्ष में 5690 करोड़ रुपये लागत की 36 लघु सिंचाई योजनाएँ (एक वृहद सिंचाई योजना) स्वीकृत कर राज्य सरकार ने खेती को समृद्ध बनाने के संकल्प को पूरा किया है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसी अवधि में 74 लघु योजनाए भी पूर्ण की गई हैं, जिनसे 26 हजार 277 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ी है। इसके अलावा, निर्माणाधीन वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित हुई है। इसी अवधि में सी.बी.आई.बी. नई दिल्ली द्वारा प्रदेश की मोहनपुरा बहुउद्देश्यीय परियोजना को समय पर पूर्ण करने तथा निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करने पर बेस्ट कंस्ट्रक्शन एन्टिटी (सर्वश्रेष्ठ निर्माण इकाई) के रूप में पुरस्कृत किया गया है।

प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है कि किसान चिन्ता-मुक्त हो, उसके पास आमदनी के स्थाई इंतजाम हो और उसे समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग भी मिले। मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रारंभिक अल्प-काल में ही इस दिशा में क्रांतिकारी फैसले लिये हैं और उन्हे जमीनी स्तर पर लागू भी किया है। सरकार ने अपने वचन-पत्र में किसान कल्याण और कृषि विकास के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों को पीढ़ियों के कर्जो से मुक्ति दिलाई है। साथ ही यह क्रम तब तक जारी रखने का संकल्प भी लिया है, जब तक प्रत्येक पात्र किसान कर्ज-मुक्त नहीं हो जाता। किसान को फसल बोने से लेकर फसल बेचने तक के काम में राज्य सरकार मदद कर रही है। बिजली, पानी आदि भी किसानों को रियायती दरों पर दिया जा रहा है।

5 साल में 12 लाख हे. में सिंचाई क्षमता का लक्ष्य

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सिंचाई क्षमता में अगले 5 साल में 12 लाख हेक्टेयर की वृद्धि की जाएगी। इस तरह सिंचाई की वर्तमान क्षमता 33 लाख हेक्टेयर को बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। साथ ही, अगले 5 साल तक सिंचाई जल की दरों को स्थिर रखा जाएगा। राज्य सरकार ने जल उपभोक्ता

संस्थाओं के निर्वाचन की अवधि को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है।

जल क्षति रोकने के लिये नहरों की लाइनिंग

प्रदेश में किसानों की सहभागिता से मार्च 2019 की स्थिति में 2064 जल उपभोक्ता संस्थाओं के माध्यम से 24 लाख 74 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। नवीन योजनाओं में नहरों में लाइनिंग का प्रावधान किया गया है। इससे जल की क्षति को रोकने में मदद मिलेगी। तवा एवं बारना वृहद परियोजनाओं में पिछले एक वर्ष में क्रमशः 116.34 किलोमीटर एवं 113.51 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य किया गया है। वर्तमान ममें 114 लघु सिंचाई योजनाओं के डीपीआर तैयार करने की कार्रवाई भी जारी है।

बांधों के जल से तालाबों का भराव

प्रदेश में जल की मांग एवं बांधों में अतिरिक्त जल की उपलब्धता के आधार पर गंगा-कछार रीवा के 112 तालाबों को बाणसागर के बांध के जल से भरा जा रहा है। इसी तरह, यमुना कछार ग्वालियर के 14 तालाबों को विभिन्न नहरों से तथा टीकमगढ़ जिले में हरपुरा नहर से क्षेत्र के 10 तालाबों को भरा जा रहा है। जल संसाधन विभाग के आधिपत्य के सभी चंदेल कालीन और अन्य प्राचीन तालाबों का रख-रखाव भी नियमित रूप से किया जा रहा है। छतरपुर तथा टीकमगढ़ जिले के 30 प्राचीन तालाबों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना

प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना लागू कर किसानों को ऋण-मुक्त करने का अभियान चलाया गया है। पहले चरण में 20 लाख 22 हजार 731 पात्र किसानों के 7154 करोड़ 36 लाख रूपये के ऋण माफ किये गये हैं। शीघ्र प्रारंभ किये जा रहे दूसरे चरण में 12 लाख से अधिक ऋण खाताधारक पात्र किसानों के ऋण माफ किये जाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जय किसान समृद्धि योजना

प्रदेश में 5 मार्च 2019 को जय किसान समृद्धि योजना लागू की गई है। इस योजना में रबी सीजन 2019-20 के लिए कृषि उपज मंडी और ई-उर्पाजन

केंद्र के माध्यम से किसान द्वारा विक्रय किये गये गेहूँ पर 160 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य सरकार ने कुल 92 लाख 67 हजार मीट्रिक टन गेहूँ विक्रय करने वाले कुल 11 लाख 79 हजार किसानों को कुल 1463 करोड़ 42 लाख प्रोत्साहन राशि देने की पुख्ता व्यवस्था की है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये शुद्ध के लिए युद्ध

राज्य सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विरासत में मिली बदहाल स्थिति को समृद्धता की ओर ले जाने का निश्चय किया है। किसानों को हर कदम पर हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही है। गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में %%शुद्ध के लिए युद्ध%% अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान न सिर्फ बीज, उर्वरक और कीटनाशक के मानक स्तर का परीक्षण किया जा रहा है बल्कि कम मात्रा में सामग्री विक्रय, अनाधिकृत विक्रय, कालाबाजारी, अधिक मूल्य पर विक्रय आदि पर भी गंभीरता से कार्यवाही की जा रही है।

मंडियों में नगद भुगतान की व्यवस्था

कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों को उनकी उपज बेचने पर दो लाख रूपये तक के नगद भुगतान की व्यवस्था की गई है। बैंकों से एक करोड़ रूपये से अधिक नगद आहरण पर टीडीएस कटौती के आयकर प्रावधानों से मंडियों में नगद भुगतान कठिनाई आई, तो तुरंत भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। इस तरह मंडी व्यापारियों को इस प्रावधान से मुक्त कराने की पहल की गई है।

ई-नाम योजना से जुड़ी कृषि उपज मंडियाँ

राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार द्वारा 25 कृषि उपज मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ा गया है। मंडी बोर्ड द्वारा 16 अगस्त, 2019 से प्रदेश की सभी मंडियों में एक साथ ई-अनुज्ञा प्रणाली लागू कर 4 लाख से ज्यादा ई-अनुज्ञा जारी किये गए हैं। इससे मण्डी व्यापारियों का समय बचा है। प्रदेश में 27 मण्डी प्रांगण में सोलर एनर्जी प्लांट भी स्थापित किये गये हैं। कृषकों को मण्डी प्रांगण में संतुष्टि अनुरूप मूल्य प्राप्त नहीं होने पर चार माह की निःशुल्क सुविधा और 80 प्रतिशत राशि कृषि उपज का भुगतान करने के लिये कोलेटेरल मैनेजमेंट एजेंसीस के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

किसानों को सस्ती बिजली

प्रदेश में किसानों के लिये दस हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप की विद्युत दरों को आधा कर दिया गया है। पूर्व मे निर्धारित 1400 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रतिवर्ष कृषि पंप की विद्युत दर को अब आधा कर 700 रूपये कर दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में प्रति कृषि उपभोक्ता लगभग 47 हजार रूपये प्रति वर्ष सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक 2622 करोड़ 53 लाख रूपये सब्सिडी प्रदान की है। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक 20 लाख 10 हजार कृषि पंपों के लिए करीब 6138 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के अतिरिक्त अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं की विद्युत दरें भी कम की गई हैं।

अजजा/अजा किसानों को निःशुल्क बिजली

प्रदेश में अब एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 5 हार्सपॉवर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिये निःशुल्क बिजली दी जा रही है। इसके एवज में राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 3800 करोड़ रूपये वार्षिक सब्सिडी देगी।

जैविक खेती

जैविक खेती के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में नंबर-वन राज्य बन गया है। एपीडा के अनुसार प्रदेश में 2 लाख 13 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, गेहूँ, धान, अरहर, चना, सोयाबीन इत्यादि फसलों की जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती के दृष्टिकोण से गौ-शालाएँ बेहद महत्वपूर्ण हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर गौ-शालाओं का निर्माण कराया जा रहा है।

राइट टू वाटर एक्ट बनाने वाला पहला प्रदेश

राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में राइट-टू-वाटर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधानसभा के आगामी बजट सत्र में यह एक्ट पारित करवाकर लागू कर दिया जाएगा। इस एक्ट के लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ लोगों को पानी का कानूनी अधिकार मिलेगा। इस कानून को लागू करने के लिये बजट में एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह एक्ट सरकारी कानून न होकर जनता का कानून होगा। इसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जल- संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों को बड़े अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जायेगा। इस कानून से प्रदेश के सभी जल-स्त्रोतों, नदियों, तालाबों और परम्परागत जल-स्त्रोतों कुएँ-बावड़ी आदि को संरक्षित कर स्थायित्व दिया जायेगा। राज्य सरकार ने प्रत्येक परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुरूप जल उपलब्ध करवाने से निश्चय का ही परिणाम है पानी का कानूनी अधिकार।

हर घर पहुँचेगा नल से जल

ग्रामीण अंचलों में हर घर तक नल से जल पहुँचाने के लिये 68 हजार करोड़ रूपये की विस्तृत कार्य- योजना बनाई गई है। अभी तक 19 समूह जल योजनाएँ पूर्ण कर 802 गाँवों की लगभग साढ़े 11 लाख से अधिक जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शन द्वारा जल-प्रदाय शुरू कर दिया गया है। रूपये 6672 करोड़ की लागत की 39 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जो अगले दो साल में पूरा हो जाएगा। इससे 6091 गाँवों की लगभग 64 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा।

मेले का टर्नओवर इस वर्ष एक हजार करोड़ रूपए करें: सिंधिया

ग्वालियर। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर के मेले की पहचान प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में है। इस ऐतिहासिक मेले में पशु मेले के साथ-साथ हर प्रकार की खरीददारी के लिए सैलानी आते हैं। ग्वालियर व्यापार मेले का टर्न ओवर गत वर्ष से 450 करोड़ रूपए था। इसे अब एक हजार करोड़ रूपए किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ग्वालियर व्यापार मेले की दुकानों का आवंटन भी अगले वर्ष से ऑनलाइन किया जाए। मेले में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सैलानियों को रात में विश्राम के लिए धर्मशाला का निर्माण भी मेला प्राधिकरण करे।

श्रीमंत माधवराव सिंधिया ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, पशुपालन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, विधायक श्री मुन्नालाल गोयल, विधायक श्री प्रवीण पाठक, मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रशांत गंगवाल, पूर्व विधायक श्री रमेश अग्रवाल, श्री रामबरन सिंह, श्री मदन कुशवाह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेन्द्र शर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष श्री मोहन सिंह राठौर, मेला सचिव श्री प्रवीण अग्रवाल, संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा, एडीजी श्री राजाबाबू सिंह, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन एवं नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन सहित मेला प्राधिकरण के सदस्यगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष वाहनों के रोड़ टैक्स पर 50 प्रतिशत की छूट दी है। इससे मेले में आकर्षण बढ़ेगा। ग्वालियर मेले में रोड़ टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्रीमंत सिंधिया ने कहा कि 114 वर्ष पुराना ग्वालियर का यह ऐतिहासिक मेला दिन-प्रतिदिन विकसित हो और देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी पहचान स्थापित कर सके, इसके प्रयास हम सबको करना चाहिए। पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेले में आने वाले व्यापारियों और सैलानियों की सुविधाओं का ध्यान भी मेला प्राधिकरण रखे। उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने 114 साल पूर्व पशु मेले के रूप में इसकी स्थापना की थी। तब यह सोच थी कि किसानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें। उनको उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। साथ ही एक ही स्थान पर सभी पशुओं का क्रय-विक्रय भी हो सके। सिंधिया परिवार ने उस समय अन्नदाताओं के लिए रेल सुविधायें उपलब्ध कराई। इसके साथ ही किसानों के लिए सबसे जरूरी पानी की उपलब्धता के लिए तिघरा और हरसी जैसे बांधों का निर्माण भी कराया।

सौ साल बाद भी तिघरा और हसी बांध आज भी किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गलत कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाने के साथ-साथ माफियाओं के विरूद्ध भी अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गलत कार्य करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो, परंतु गलत कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाना चाहिए।

अगले वर्ष से मेले की दुकानों का आवंटन हो ऑनलाईन, श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेले का भव्य शुभारंभ

मेहगांव के ग्राम नागदा गौशाला का लोकार्पण, 10 किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रदान, तीन स्थानों पर दुग्ध केन्द्र खुलेंगे

दस लाख निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में रखा जावेगा

मप्र शासन पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने कहा है कि मप्र सरकार निराश्रित गौवंश को रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जिसमें प्रथम चरण के दौरान एक हजार गौशाला बनाने का लक्ष्य रखा है। वे मेहगांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत पैचरा में आदर्श गौशाला के लोकार्पण समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गौमाता को गौशाला में प्रवेश भी कराया।

इस अवसर पर मेहगांव क्षेत्र के विधायक श्री ओपीएस भदौरिया, भिण्ड विधायक श्री संजीव सिंह, गोहद विधायक श्री रणवीर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामनारायण हिण्डोलिया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री जयश्रीराम बघेल, कलेक्टर श्री छोटेसिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर, सरपंच पचेरा श्रीमती पूनम बंटी त्यागी, पार्टी पदाधिकारी श्री अशोक शर्मा, एसडीएम श्री गणेश जायसवाल, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ. एएस तोमर, उप संचालक डॉ एनएस सिकरवार विभागीय

अधिकारी, त्रिस्तरीय पचायतो के पदाधिकारी, तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि चंबल संभाग के भिण्ड जिले में आज पहली गौशाला का लोकार्पण किया गया है। इस गौशाला में निराश्रित गौवंश को रखने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होने कहा कि गौशाला के नोंरम के अनुसार सुविधाएं इस गौशाला में उपलब्ध रहेगी। उन्होने कहा कि मेहगांव क्षेत्र की पचैरा गौशाला में निराश्रित गौवंश को रखने की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है। जिसका संचालन पचैरा ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा।

भिण्ड जिले में गौ अभ्यारण बनाया जावेगा

भिण्ड। पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री लाखन सिंह यादव एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविन्द सिंह की उपस्थिति में निर्माणाधीन गौशालाओं की समीक्षा बैठक आज कलेक्टर कार्यालय भिण्ड के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में भिण्ड जिले में गौ अभ्यारण बनाने एवं लंबित अविवादित नातांतरण, बटवारे के प्रकरणों का निराकण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मेहगांव क्षेत्र के विधायक श्री ओपीएस भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रामनारायण हिण्डोलिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री जयश्रीराम बघेल, कलेक्टर श्री छोटेसिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री आईएस ठाकुर एवं पंचायतो के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। पशुपालन मंत्री श्री लाखन सिंह यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गौ अभ्यारण बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इस अभ्यारण में ढाई हजार से लेकर पांच हजार तक निराश्रित गौवंश को रखने की सुविधा प्राप्त होगी।

जिसके लिए 20 रूपए प्रति केटल के मान से राशि प्रदान की जाएगी। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि भिण्ड जिले में करीबन 25 हजार अविवादित नामांतरण, बटवारा के प्रकरण लंबित है। इनके निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान फरवरी अंत तक चलेगा। साथ ही अविवादित नामांतरण, बटवारा के प्रकरण को शून्य पर लाया जाएगा।

इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेहगांव क्षेत्र के विधायक श्री ओपीएस भदौरिया ने गौवंश के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। साथ ही अविवादित नामांतरण, बटवारा के निराकरण के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। बैठक में कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने कहा कि प्रथम चरण के अन्तर्गत गौशालाओं के निर्माण का कार्य 30 जनवरी 2020 तक पूर्ण कराने के प्रयास किए जाएंगे। गौ अभ्यारण के लिए जमीन का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण, बटवारा के लिए अभियान चलाकर राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से माह फरवरी तक कार्य को पूर्ण कराया जाएगा।

दैनिक जीवन में किसी से द्वेष नहीं रखें, विश्व कल्याण की बात करें: मोरारी बापू

भिंड। हमें किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। हमें विश्व कल्याण के मंगल के लिए अध्ययन करना है। साधु को प्रेम करने से कोई हानि नहीं होती। साधु, साधु रहता है विभीषण जैसे सज्जन साधु को लात मारने से रावण का क्या हुआ, यह आप सभी जानते हैं। रातवुपरा धाम में मंगलवार को रामकथा के 4वें दिन यह बात राष्ट्र संत मोरारी बापू ने कही। कथा के लिए बापू संत रविशंकर महाराज के साथ पूजा व्यासपीठ पहुंचे। रविशंकर महाराज ने श्रद्वालुओं, संतों के साथ बैठकर रामकथा सुनी। रामकथा में मोरारी बापू ने कहा भगवान शिव धर्म का मूल हैं। सनातन धर्म की जड़ शिव हैं। शिव धर्म की जड़ हैं। शिव की आलोचना करोगे तो क्या धर्म बचेगा कोई खुलकर गर्जना करेगा तो उसका क्या होगा यह वो ही जाने, हमें तो द्वेष मुक्त संदेश देना है। यह साधु का कर्तव्य है। बापू ने कहा पवन तनय के यह पांच तत्व जिसमें होंगे, वही चरित्रवान होगा। पांच तत्वों की शुद्धि को चरित्र कहते हैं। कर्म शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि, वचन शुद्धि। यह 5 तत्व, जिसमें होंगे वो चरित्रवान होगा। कर्म शुद्धि अर्थात आपके कर्म से दूसरों को लाभ मिले। द्रव्य शुद्धि अर्थात अपने लाभ का 10 प्रतिशत दान देने से द्रव्य शुद्धि होती है। बापू ने कहा

अगर भूख लग रही है तो क्या आप नोट खाओगे। आपको अपने पैसों से भोजना खरीदना ही पड़ेगा। अमेरिका जैसे देश में जाकर भी अपनी मुद्रा का परिवर्तन कराना पड़ती है। क्या यह नोट ऊपर चलेगा इसलिए परिवर्तन कराने के लिए अपने लाभ का 10 प्रतिशत दान देना ही पड़ेगा। बापू ने कहा मैं जहां-जहां भी रामकथा करता हूं, हर जगह द्रव्य दान की बात करता हूं। लोगों ने मानना शुरू किया है। मंत्र शुद्धि राम मंत्र जैसा पवित्र मंत्र इस दुनिया में नहीं है। चित्त शुद्धि भगवान हनुमान का मन रावण के स्वर्ण महल में भी नहीं डोलता, यह चित्त शुद्ध है। वचन शुद्धि ऐसे प्यारे बोल बोलना चाहिए, जिससे सबका मन खुश हो जाए। अशोक वाटिका में माता सीता से जो संवाद हनुमान जी का हुआ है। वह वचन शुद्धि का सबसे बडा उदाहारण है। रामचरित्र मानस पवित्र वैज्ञानिक ग्रंथ बापू ने कहा पवन तनय का पर्याय शब्द ब्रह्माहै। ब्रह्म को लेकर हम स्वात्तिक संवाद कर रहे हैं। वायु के नाम प्रभंजन, समीर, पवन हैं। पवन से पैदा होने वाले का नाम भी पवन तनय है। पवन से ही सूर्य का जन्म होता है। बांसुरी भी पवनजय है। पवन गतिशील है। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं समीर वायु, हवा, पवन, मारूति यह सृष्टि के रत्न हैं। जब भगवान श्रीराम का प्रारब्ध होता है तब इन्द्र सहित सारे देवता व हनुमान जी उपस्थित थे। भगवान राम जब वनवास गए तब ऋषि भारद्वाज के आश्रम से उनके चार शिष्यों के साथ आगे बढते हैं। कुछ दूर जाकर वह निषादराज को विदाई देते हैं। यह कर्तव्य बोध कराता है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं उसके बाद तापस का प्रवेश होता है। बाद में विद्वान खोज करते हैं, उस तापस का नाम क्या है?

दंदरौआ धाम में श्रीमद् भागवत् कथा का आयोजन

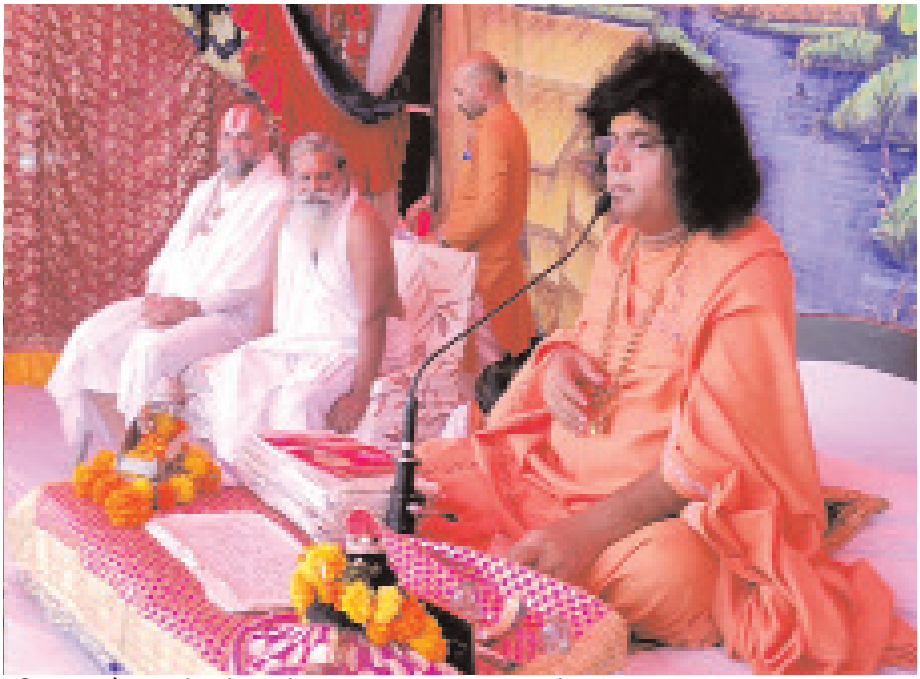

भिण्ड। दंदरौआधाम में गुरुदेव पुरुषोत्तमदास महाराज की पुण्यतिथि 23वे सिय-पिय मिलन समारोह के अवसर पर श्री 1008 महामण्डलेश्वर श्री रामदास जी महाराज के सानिध्य में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है। भागवत कथा के तृतीय दिन रविवार को व्यास गद्दी से परम पूज्य संत आचार्य श्री कौशिक जी महाराज वृन्दावन धाम ने कहा कि जो मनुष्य ईश्वर से दूर रहता है वह मनुष्य मायाजाल में फस जाता है लेकिन जो मनुष्य परमात्मा के चरणों में रहता है उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। संसार एक नदी ईश्वर उस नदी का मछुआरा है ईश्वर के मायाजाल में जीव फंस जाता है वह मनुष्य मायाजाल से बच नहीं पाता जो ईश्वर से दूर रहते हैं इसलिए मनुष्य को ईश्वर के शरण रहना चाहिए। व्यक्ति अपने परिवार के लिए दुखी होता है लेकिन संत समाज के कल्याण के लिए दुखी होता है बड़भागी कौन है जो मनुष्य ईश्वर और धर्म से जुड़े रहते है वह बड़भागी है जो व्यक्ति ईश्वर से दूर रहते हैं संसार के भोगों में लिप्त रहते हैं वह अभागी होते है। अगर मनुष्य गुरुजनों और महापुरुषों की सेवा से जुड़े हैं तो वह भाग्यशाली है वह परिवार कभी नहीं बिखर सकते हैं जिनमें सत्य, प्रेम, करुणा हैं हमारे जीवन में ईमानदारी का वर्चस्व होना चाहिए जो व्यक्ति सत्य पर चलता है वह ऐसा होता है जैसे मोती की माला में हीरा अलग चमकता है। अपने परिवार में सत्य, प्रेम, करूणा की स्थापना करें। भागवत कथा में मंहत श्री रामभूषणदास महाराज खनेता, दंदरौआ धाम के व्यवस्थापक श्री श्री 108 महंत राधिकादास महाराज, रामनरेश करैया, जलज त्रिपाठी, रामहरी शर्मा,अशोक भारद्वाज सहित लाखों की संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे।

विकास के कार्य समन्वय के साथ शीघ्र हों

ग्वालियर। शहर विकास के कार्यों को सभी के समन्वित प्रयास से तेजी के साथ किया जाए। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र लोगों को समय पर मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। शहर विकास के कार्यों में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा कर कार्य को और गति प्रदान करने के प्रयास किए जाना चाहिए। क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं।

कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में शहर विकास के अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए गए। बैठक में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मनीषा भुजवल सिंह यादव, विधायक श्री मुन्नालाल गोयल, विधायक श्री प्रवीण पाठक, विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रतिनिधि एवं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष श्री कृष्णराव दीक्षित, मंत्री श्री लाखन सिंह यादव के प्रतिनिधि सहित नगर निगम कमिश्नर श्री संदीप माकिन, सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा, एडीएम श्री टी एन सिंह, सीईओ स्मार्ट सिटी श्री महिप तेजस्वी सहित समिति के सदस्यगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में स्वर्ण रेखा नदी के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। सांसद श्री शेजवलकर ने कहा कि स्वर्ण रेखा में मिलने वाले 84 नालों को किस प्रकार सीवर से जोड़ा जायेगा तथा स्वर्ण रेखा के दोनों ओर किस प्रकार से सड़क का निर्माण किया जाकर यातायात प्रबंधन किया जायेगा। इसका विस्तृत प्लान तैयार कर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर तत्परता से किया जाना चाहिए। अमृत परियोजना के तहत भी किए जा रहे कार्यों में सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी देकर तेजी से कार्य हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विधायक श्री प्रवीण पाठक एवं श्री मुन्नालाल गोयल ने भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की और कार्यों को तेजी के साथ करने की बात कही।

जलविहार में हुई पार्षदों को विदाई, दो दशक पुरानी परंपरा टूटी

ग्वालियर. नगरीय निकायों के चुनाव टलने के कारण नई परिषद के शपथ ग्रहण और पहली बैठक की दो दशक पुरानी परंपरा टूट गई। चुनाव टलने की वजह से नगरनिगम की नई परिषद की पहली बैठक 11 जनवरी को नहीं होगी। 20 साल से हर बार नई परिषद के पार्षद और महापौर 10 जनवरी को शपथ लेने के बाद 11 जनवरी को सभापति का चुनाव करने के लिए परिषद में एकत्र होते थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा।

पिछली परिषद तक महापौर का चुनाव सीधा होने के कारण परिषद में सिर्फ सभापति का चुनाव हुआ था। इस बार सभापति के साथ महापौर का चुनाव भी पार्षदों द्वारा ही किया जाएगा लेकिन पिछली परिषद का कार्यकाल शुक्रवार को समाप्त होने और निकाय चुनाव टलने के कारण अब अगली परिषद की बैठक कब होगी यह तय नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही तय करना है कि चुनाव कब होंगे। निकाय चुनाव के संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई 16 जनवरी को जबलपुर हाईकोर्ट में होगी फिलहाल राज्य सरकार परिषद में प्रशासक नियुक्त करेगी। शुक्रवार को जलविहार में हुए विदाई समारोह में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को निगमायुक्त संदीप माकिन के लिए इंतजार करना पड़ा। वह देरी से पहुंचे इसलिए कार्यक्रम ढ़ाई बजे शुरू हो पाया। सांसद ने पार्षदों को नसीहत दी कि जनता की सेवा का संकल्प जो आपने लिया है वह कभी नहीं छोड़ना। विधायक प्रवीण पाठक ने कहा सांसद हो या विधायक का सफल कार्यकाल पार्षद के सहयोग से ही होता है। सभापति राकेश माहौर ने कहा कि परिषद के संचालन में सभी दलों के सदस्यों को सीखने को मिला है। कांग्रेस पार्षद दल के नेता कृष्णराव दीक्षित ने कहा पांच साल के दौरान बड़ी-बड़ी योजनाओं को स्वीकृति मिली। इसका फायदा भविष्य में जनता को होगा। आयुक्त संदीप माकिन ने कहा कि परिषद का कार्यकाल तकनीकी रूप से खत्म हो रहा है। विकास के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। इस मौके पर पार्षदों को स्मृति चिन्ह शाल और श्रीफल भेंट किए गए।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की बैठक संपन्न

ग्वालियर। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा गोले के मंदिर स्थित इंद्रप्रस्थ गार्डन में मीटिंग आयोजित की गई जिसका मुख्य मुख्य उद्देश्य था संगठन में एकता और मजबूत करना कार्यक्रम के मुख्यातिथि राष्ट्रीय संगठन अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह तोमर उपस्थित रहे साथ ही राजीव भदौरिया ज़िला अध्यक्ष रामकुमार सिंह सिकरवार जितेंद्र कुशवाह अशोक तोमर रेशु राजावत शकुंतला परिहार राजाराम महेन्द श्याम सिंह तोमर उपस्थित रहे साथ ही नई नियुक्तियां भी की गई वरिष्ठ पदाधिकारी के नेत्रत्व में प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदोरिया को बनाया गया साथ ही धनेंद्र चौहान,संजय जादौन को प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन तोमर भिडौसा को प्रदेश संगठन महामंत्री रोहित तोमर,शेखर भदौरिया,शैलेंद्र भदौरिया संगठन मंत्री धर्मेंद्र चौहान,प्रीत तोमर को प्रचार मंत्री,भरत सिंह

चौहान प्रदेश मीडिया प्रभारी वही ग्वालियर संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज सिंह सोलंकी अंजना चौहान ग्वालियर संभाग महांमत्री एवं तन्वी चौहान मीडिया प्रभारी को बनाया गया युवा जिलाध्यक्ष राजू सिकरवार डॉ अर्जुन सिंह ज़िला उपाध्यक्ष गोपाल तोमर उपाध्यक्ष सतेंद्र तोमर,महेश सिकरवार ज़िला मंत्री,संजू राठौर,मेनी सिंह तोमर को महामंत्री बनाया गया संभाग में शेरू चौहान,हेमन्त भदौरिया, सर्वेश तोमर को उपाध्यक्ष, डॉ जय सिंह तोमर,हरीश भदौरिया, मोती परमार,विक्रम तोमर को संगठन मंत्री भूपेंद्र पवैया आदि लोगों को मनोनीत किया गया कार्यक्रम का संचालन श्याम सिंह तोमर ने किया अंत मे सभी के लिये सुलपहार की व्यवस्था भी की गई थी।

आवश्यकता है

पुष्पांजली टुडे राष्ट्रीय मासिक पत्रिका/ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को भारत के हर राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है।

इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।

देश के सभी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, गोवा, झारखंड

कार्यालयः ए-ब्लॉक 404 भाऊ साहब की पोतनिस, इन्क्लेव मुरार रोड गोले का मंदिर ग्वालियर

संपर्कः 7999246560, 8269307478

Email-pushpanjalitoday@gmail.com. Web-www.pushpanjalitoday.com

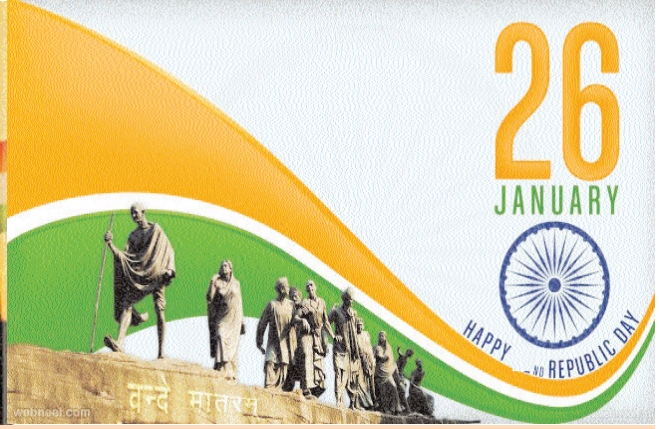

क्या हैं गणतंत्र के सही मायने

देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं। देशप्रेम की भावना से ओत-प्रोत हजारों की संख्या में भारत माता के वीर सपूतों ने, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना सर्वस्य न्योछावर कर दिया था। ऐसे ही महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश, गणतान्त्रिक देश हो सका।26 जनवरी, 1950 भारतीय इतिहास में इसलिये भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान, इसी दिन अस्तित्व मे आया और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बडा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष, 11 महिना, 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार, भारत रत्न से अलंकृत डॉ.भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इस दिन भारत एक सम्पूर्ण गणतान्त्रिक देश बन गया।देश को गौरवशाली गणतन्त्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तो ने अपना बलिदान दिया उन्हे याद करके, भावांजली देने का पर्व है, 26 जनवरी।

गणतन्त्र का अर्थ है, जनता के द्वारा जनता के लिये शासन। इस व्यवस्था को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे तो भारत में सभी पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, परन्तु गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस पर्व का महत्व इसलिये भी बढ जाता है क्योंकि इसे सभी जाति एवं वर्ग के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं।

गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? मित्रों, जब अंग्रेज सरकार की मंशा भारत को एक स्वतंत्र उपनिवेश बनाने की नजर नही आ रही थी, तभी 26 जनवरी 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरु जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्णस्वराज्य की शपथ ली। पूर्ण स्वराज के अभियान को पूरा करने के लिये सभी आंदोलन तेज कर दिये गये थे। सभी देशभकतों ने अपने-अपने तरीके से आजादी के लिये कमर कस ली थी। एकता में बल है, की भावना को चरितार्थ करती विचारधारा में अंग्रेजों को पिछे हटना पडा। अंतोगत्वा 1947 को भारत आजाद हुआ, तभी यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1929 की निर्णनायक तिथी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनायेंगे।

26 जनवरी, 1950 भारतीय इतिहास में इसलिये भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत का संविधान, इसी दिन अस्तित्व मे आया और भारत वास्तव में एक संप्रभु देश बना। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बडा संविधान है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष, 11 महिना, 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के वास्तुकार, भारत रत्न से अलंकृत डॉ.भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे लक्षणों को अपने संविधान में आत्मसात करने का प्रयास किया है। इस दिन भारत एक सम्पूर्ण गणतान्त्रिक देश बन गया।देश को गौरवशाली गणतन्त्र राष्ट्र बनाने में जिन देशभक्तो ने अपना बलिदान दिया उन्हे याद करके, भावांजली देने का पर्व है, 26 जनवरी।

अतः 26 जनवरी को उन सभी देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व भारतवर्ष के कोने-कोने में बड़े उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रति वर्ष इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती है। भारत की राजधानी दिल्ली समेत प्रत्येक राज्य तथा विदेषों के भारतीय राजदूतावासों में भी यह त्योहार उल्लास व गर्व से मनाया जाता है। 26 जनवरी का मुख्य समारोह भारत की राजधानी दिल्ली में भव्यता के साथ मनाते हैं। देश के विभिन्न भागों से असंख्य व्यक्ति इस समारोह की शोभा देखने के लिये आते हैं। हमारे सुरक्षा प्रहरी परेड निकाल कर, अपनी आधुनिक सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं तथा सुरक्षा में सक्षम हैं, इस बात का हमें विश्वास दिलाते हैं। परेड विजय चौक से प्रारम्भ होकर राजपथ एवं दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से गुजरती हुयी लाल किले पर जाकर समाप्त हो जाती है। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री 'अमर जवान ज्योति' पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपति अपने अंगरक्षकों के साथ 14 घोड़ों की बग्घी में बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण करते हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है, हवाई जहाजों द्वारा पुष्पवर्षा की जाती है। आकाश में तिरंगे गुब्बारे और सफेद कबूतर छोड़े जाते हैं। जल, थल, वायु तीनों सेनाओं की टुकड़ियां, बैंडो की धुनों पर मार्च करती हैं। 26 जनवरी का पर्व देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी समेटे हुए है। प्रत्येक भारतीय को अपने देश की आजादी प्यारी थी। भारत की भूमि पर पग-पग में उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास अंकित है। किसी ने सच ही कहा है- कण-कण में सोया शहीद, पत्थर-पत्थर इतिहास है। ऐसे ही अनेक देशभक्तों की शहादत का परिणाम है, हमारा गणतान्त्रिक देश भारत। 26 जनवरी का पावन पर्व आज भी हर दिल में राष्ट्रीय भावना की मशाल को प्रज्वलित कर रहा है। लहराता हुआ तिरंगा रोम-रोम में जोश का संचार कर रहा है, चहुँओर खुशियों की सौगात है। हम सब मिलकर उन सभी अमर बलिदानियों को अपनी भावांजली से नमन करें, वंदन करें।

आयल मसाज से दूर हो सकती है स्किन की ड्राईनेस

ठण्ड के मौसम में टेम्प्रेचर बहुत कम हो जाता है जिसके कारण स्किन में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और इसी कारण से सर्दियों के मौसम में स्किन बेजान नज़र आने लगती है, बहुत बार तो स्किन के ड्राई होने के कारण स्किन पर फाइन लाइन्स और झुर्रियां भी दिखाई देने

लगती हैं. पर अगर आप इस मौसम में अपनी स्किन की खास देखभाल करती हैं तो अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं.सर्दियों के मौसम में स्किन पर मसाज करना बहुत फायदेमंद होता है, अधिक ठण्ड पड़ने के कारण स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इसलिए इस मौसम में स्किन मसाज आपकी स्किन को बहुत सारे फायदे पहुंचा सकती है. इसलिए अगर आप सर्दियों के मौसम में भी अपनी स्किन को नरम और मुलायम बनाये रखना चाहती हैं तो हफ्ते में एक बार मसाज ज़रूर करवाए.

बालों को कोमल और मुलायम बनाता है दही

सर्दियों के मौसम में तेज और सर्द हवाओ के कारण बालों की नमी कही खो जाती है. जिसके कारण बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते है और बेजान से नज़र आने लगते है. बालों के ड्राई हो जाने के कारण बाल झड़ने लगते है और इसी कारण से बाल में डैंड्रफ की समस्या सामने लगती है. जिसके कारण बालो की पूरी खूबसूरती खो जाती है, पर आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे है जिनके इस्तेमाल से बाल कोमल हो जाते है और इनकी नेचुरल चमक वापस आ जाती है.

1- बालों के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है, बालों की जड़ो में नारियल का तेल लगाने से बाल मजबूत बनते है, और साथ ही इनकी ड्राईनेस भी दूर हो जाती है, अगर आप अपने बालों को कोमल,चमकदार और खूबसूरत बनाना चाहती है तो

इसके लिए हफ्ते में दो बार अपने बालो की मसाज नारियल के तेल से करे, और मसाज करने के दो घंटे के बाद अपने बालो को शैम्पू से धो दे.

बच्चों को पिलाएं ग्राइप वाटर, मिलेंगे फायदे

ग्राइप वाटर बच्चों को शुरूआती दिनों में दिया जाता है। हालांकि इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ग्राइप वाटर में एल्कोहल का इस्तेमाल हुआ करता था लेकिन इन दिनों ग्राइप वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बच्चों के पेट से गैस निकालने में मदद करता है। इसके अलावा, नवजात बच्चा पूर्ण रूप से मां के दूध पर निर्भर होता है। कुछ स्थितियों में बच्चे को बाहरी चीजों की जरूरत

भी होती है, जिस वजह से बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाया जाता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे की शिशु को ग्राइप वाटर पिलाने से क्या फायदा मिलता है। वैसे तो ग्राइप बोतल पर शिशु को पिलाने की मात्रा बताई होती है लेकिन अपने शिशु को ग्राइप वाटर पिलाने से पहले डॉक्टरी से उसके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी लें। फिर डॉक्टर से ही पूछ कर बच्चों को पर्याप्त मात्रा में ग्राइप वाटर पिलाएं।

इंस्टेंट निखार पाने के लिए चेहरे पर लगाए सेब का फेस मास्क

ये बात तो आप सभी जानते है सेब हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है, सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, सी और कॉपर मौजूद होते है जो इसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद बनाने का काम करते हैं, पर क्या आपको पता है की सेब ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. आज हम आपको सेब के कुछ ऐसे फेस मास्क के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप सांवलेपन से भी छुटकारा पा सकते है.

1- अगर आप अपने सांवलेपन से छुटकारा पाना चाहती हैं तो इसके लिए सेब को पीसकर पेस्ट बना लें, अब इसमें दही और एक चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाये और इसे अपने चेहरे पे लगाएं, 15 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धों लें. कुछ दिनों तक लगातार इसके इस्तेमाल से आपका रंग गोरा हो जायेगा.

2- अपनी रुखी और बेजान त्वचा में नयी जान लाने

के लिए सेब के पेस्ट में ग्लिसरीन की कुछ बूंदो को डालकर अच्छे से मिक्स करे और अपने चेहरे पर लगाएं. 20 मिनट के बाद इस पेस्ट को गर्म पानी से धो लें.

3- अगर आप अपने चेहरे पर निखार लाना चाहती हैं तो सेब के पेस्ट में अनार का जूस और दही डालकर अच्छे से मिलाएं और फिर इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें, अब गर्म पानी से चेहरा धो लीजिए. ऐसा करने से आपको इस्टेंट निखार मिल जाएगा.

अमिताभ बच्चन को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दादासाहेब फाल्के पुरस्कार बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता अमिताभ बच्चन को प्रदान किया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया।इस दौरान अमिताभ की पत्नी जया बच्चन और बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। अवॉर्ड लेने के बाद अमिताभ ने मजाक में एक सवाल किया कि कहीं यह पुरस्कार मिलना इस बात का संकेत तो नहीं कि मैं अब घर बैठकर आराम करूं? इस बात पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। 23 दिसंबर को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण हुआ था। उस दौरान अमिताभ खराब सेहत के चलते यह सम्मान नहीं ले पाए थे। तब उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फिल्म अवॉर्ड्स का वितरण किया था। अवॉर्ड लेने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा, ÷मैं सरकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और जूरी के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। मुझ पर ईश्वर की कृपा रही है और माता-पिता का आशीर्वाद रहा है। निर्माता-निर्देशकों और सह-कलाकारों का साथ रहा। सबसे ज्यादा भारत की जनता का स्नेह और प्रोत्साहन रहा, जिसकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। इस पुरस्कार की स्थापना 50 साल पहले हुई और इतने ही साल मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। इसका भी मैं आभारी हूं। इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के सभी विजेता राष्ट्रपति भवन में पहुंचे। अमिताभ के साथ पत्नी जया और बेटे अभिषेक बच्चन भी मौजूद रहे।

2020 में टीम इंडिया के सामने होगी ये बड़ी चुनौती

भारतीय खेलों के लिये नया साल 2020 बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है और भारतीय खेलों को अपनी दिशा तय करने के लिये नये साल में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक में अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। साल 2020 में भारतीय खेलों के लिये टोक्यो ओलंपिक के बाद आस्ट्रेलिया की मेजबानी में होने वाला 20-20 विश्वकप भी खासा महत्वपूर्ण होगा। नया साल कई ओलंपिक पदक विजेताओं के भाग्य को तय करेगा और जबकि नये सितारों का इस साल उदय भी होगा। भारत ने 2016 के पिछले रियो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन किया था और एक रजत और एक कांस्य के रूप में मात्र दो पदक जीते थे। रियो के इस प्रदर्शन के बाद सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुये अगले तीन ओलंपिक के लिये तुरंत योजना बनाने के निर्देश दिये थे ताकि 2028 के ओलंपिक तक भारत अपने प्रदर्शन को नयी ऊंचाइयों पर ले जा सके। भारत की यह भी कोशिश है कि वह 2032 के ओलंपिक की मेजबानी हासिल करे। लेकिन इससे पहले उसे अपने प्रदर्शन को विश्व स्तर के अनुरूप लाना होगा।

भारतीय क्रिकेट के लिये 2019 बेहद शानदार साल रहा था। इस साल विश्वकप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली नाकामी को छोड़ दिया जाए तो विराट कोहली एंड कंपनी के लिये खेल के तीनों फार्मेट में यह साल जबरदस्त रहा। हालांकि साल के अंत में कप्तान विराट और सीमित ओवरों के उपकप्तान रोहित शर्मा ने माना कि विश्वकप के वो 30 मिनट उन्हें हमेशा याद रहेंगे। इस 30 मिनट के समय में भारतीय टीम ने विराट, रोहित और लोकेश राहुल के विकेट गंवाये थे जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें समाप्त हो गयीं। बल्लेबाजी में लीजेंड का दर्जा हासिल कर रहे विराट भारत के सबसे सफल कप्तानों में तभी शुमार हो पाएंगे जब वह 2020 में होने वाले टी-20 विश्वकप में भारत को कामयाबी दिलाएंगे।

आरोही कान्हा इन्टरप्राइजेज

तोमर टाइल्स

टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल के थोक विक्रेता

राहुल तोमर: 96930448042 रोहित तोमर: 94257778466

पता: चार शहर का नाका, सागरताल रोड, सोना गार्डन के सामने ग्वालियर

सलमान संग काम करने का इंतजार कर रहीं दीपिका

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने सलमान खान के साथ एक फिल्म करने की संभावना पर खुलकर बोला है और खुलासा किया है कि वह अपनी आगामी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग मार्च में शुरू करेंगी, जिसमें अनन्या पांडे और गली ब्वॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी भी हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक कार्यक्रम में अपनी अगली फिल्म छपाक के प्रचार के दौरान कहा, मैं अपनी अगली फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ काम कर रहा हूं, जो शकुन बत्रा द्वारा निर्देशित है। हम इसकी शूटिंग मार्च में शुरू कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह छपाक के प्रचार के लिए सलमान खान के शो बिग बॉस में जाएंगी तो उन्होंने कहा, नहीं, बिग बॉस में जाने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। इसके बाद उन्होंने वह कहा जिसे कई प्रशंसक सुनना चाहते थे। अभिनेत्री ने कहा, ‘हमारे प्रशंसक हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहते हैं कि क्या हम एक साथ एक फिल्म कर रहे हैं, या हम कब साथ में फिल्म कर रहे हैं। मैं वास्तव में इसे करना चाहती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए सही तरह की फिल्म के लिए साथ आना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने हमेशा सलमान को कुछ विशेष प्रकार की फिल्मों में देखा है। उन्होंने कहा, मैं हम दिल दे चुके सनम की सबसे बड़ी प्रशंसक हूं और मैं उन्हें इस तरह की भूमिका में देखना चाहूंगी या उन्होंने जो किया है, उससे कुछ अलग देखना चाहूंगी इसलिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में पटकथा है (जो मायने रखता है)। हमें हाल के दिनों में साथ में काम करने के प्रस्ताव नहीं मिले हैं, लेकिन मैं उनके साथ एक फिल्म करना पसंद करूंगी।